RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

धूल की तरह उड़ती है अफवाहें, सत्य जानने के लिए सब्र करना पड़ता है।

विकास दिव्यकिर्ति

वर्ष-08, अंक - 33 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 04 जून 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

अभिनंदनलाल v/s टपोरीलाल... भाषाई मर्यादा ना भूले माननीय

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

लोकतंत्र में आलोचना और घृणा में बहुत अंतर होता है। आप सत्ता के आलोचक हो सकते हैं लेकिन घृणा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आलोचना मुद्दे आधारित होना चाहिए और तथ्य परक तथा तीखी आलोचना सत्ता को निरंकुश होने से रोकती हैं। और इसीलिए कहा गया है कि, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही गाड़ी में पहिए के समान आवश्यक है और भारत के लोकतंत्र में तो पक्ष द्वारा विपक्ष का सम्मान किया जाना स्वस्थ्य परंपरा रही है। वहीं विपक्ष भी भले ही सत्ता पक्ष का कटु आलोचक रहे मगर जहां बात सम्मान की आती है तो वह हमेशा ही सत्ता पक्ष का सम्मान करता रहा है। अटल जी ने विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए देवी दुर्गा की संज्ञा दी थी। वहीं अटलजी को सत्ता पक्ष द्वारा इलाज के लिए विदेश भी राजीव गांधी सरकार में भेजा गया था। यानी पक्ष और विपक्ष भले ही एक दूसरे के आलोचक रहे लेकिन जब बात देश की और मर्यादा की हो तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान आदर भाव रखते आए हैं।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक बयान बाजी का स्तर बहुत नीचे स्तर तक गिरा है। जहां आलोचना को व्यक्तिगत निंदा और अपने प्रति घृणा समझा जाने लगा और एक दूसरे के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को अभिनंदनलाल की संज्ञा दी तो मुख्यमंत्री भी अपना आपा खो बैठे और मंच से सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि, हम तो अभिनंदनलाल है... लेकिन आप तो टपोरीलाल है...। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दो कौड़ी जैसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया। यह देखकर कई लोगों का कहना है कि, छोटे-छोटे बच्चे खेल-खेल में जब झगड़ पढ़ते हैं तो एक दूसरे के लिए विभिन्न प्रकार के नामो का उच्चारण करते हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी छोटे बच्चों की भाती एक दूसरे का नामकरण का खेल, खेल रहे है जो राजनीतिक मनोरंजन के लिए ठीक हो सकता है और इस प्रकार के मंचिय भाषणों से तालियां बजवाई जा सकती है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता है। इतने उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियो से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी के बाद दोनों ही दलों के अन्य नेताओं ने भी एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे मुख्यमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पुराने बयानों की क्लिप चलाकर उन्हें राजनीति मर्यादा का पाठ सिखाया।

वैसे देखा जाए तो राजनीतिक बयान बाजी का यह गीरता स्तर यकायक नहीं आया है, पिछले कुछ वर्षों में इसका स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। शीर्ष स्तर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संज्ञा को देश द्रोही तक कहा गया। जबकि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में सत्ता पक्ष की आलोचना का अधिकार विपक्ष को दिया है लेकिन जब यह आलोचना घृणा में बदल जाती हैं तो सवांद का रास्ता बंद हो जाता है। देश के सर्वोच्च कार्यकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों की ऐसी शब्दावली का प्रयोग देश के उस जनादेश का अपमान है जिसमें उन्हें चुना गया है। विपक्ष को यह समझना होगा कि, उसका कार्य सत्ता पक्ष की नीतियों का ठोस विकल्प के साथ विरोध करना है न कि पूरे तंत्र की व्यवस्था का विरोध करना। वहीं सरकार की नीतियों का विरोध देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध न बनने पाए।

वहीं कुछ समय से ऐसा भी चलन देखने में आया कि, संसद या विधानसभा सत्र के कुछ समय पूर्व कुछ सामायकि मुद्दों को लेकर कुछ बयान बाजी हो जाती है और उसी को मुद्दा बनाकर पक्ष और विपक्ष सत्र को चलने नहीं देते हैं और सत्र का संचालन बाधित होता है। जहां सार्थक और तथ्य परक बहस होना चाहिए वहां हंगामा, नारेबाजी और शोर शराबे में समय व्यतीत हो जाता है और असल मुद्दे ढण्डे बस्ते में चले जाते हैं। ऐसे में राजनेताओं को चाहिए कि, वे आलोचना को व्यक्तिगत घृणा न बनने दे, स्वस्थ और तथ्य परख आलोचना लोकतंत्र की रीढ़ है। तथा सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि, वे नीतिगत आलोचना को गंभीरता से सुने और विपक्ष के सुझाव को नजर अंदाज न करें।

कोचिंग संस्थान पर हमले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन

पटना।

चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए। छात्रों ने खान सर के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा और लंबा जाम लग गया।

प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्र-छात्राएं सड़क पर बैठ गए और घटना को लेकर नाराजगी जताई। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। इस दौरान खान सर अपने आवास की बालकनी में पहुंचे और छात्रों से शांति बनाए रखने तथा प्रदर्शन समाप्त कर घर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

खान सर ने छात्रों को बताया कि घटना के बाद पूरी रात पुलिस बल कोचिंग संस्थान के बाहर तैनात रहा और कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके बावजूद छात्र घटना को लेकर पूरी जानकारी और त्वरित कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि शिक्षक की सुरक्षा से जुड़ा मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कई छात्राओं ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि वे अपने शिक्षक के समर्थन में खड़ी हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहती हैं।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार देर रात कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्हपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने संस्थान के बाहर लगे पोस्टर फाड़े और परिसर में नुकसान पहुंचाया। विरोध करने पर सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भारत लौटेंगे अभिजीत दीपके, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

नई दिल्ली।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को भारत लौटने की घोषणा करते हुए अपने समर्थकों से हवाई अड्डे पर पहुंचने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि भारत आगमन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है।

अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने सामाजिक माध्यमों पर जारी एक वीडियो में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे प्रश्नपत्र लीक और अन्य विवादों के लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए।

दीपके ने कहा कि, उनका प्रस्तावित प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में होगा। उन्होंने बताया कि 6 जून को भारत पहुंचने के बाद वे पैदल संसद मार्ग थाना जाएंगे और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के लिए औपचारिक आवेदन देंगे।

उन्होंने दावा किया कि, उनकी वापसी के बाद कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उन्हें अपने देश लौटने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने उनके आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है।

अभिजीत दीपके ने कहा कि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों ने लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि, यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने का विषय है।

अभी तक प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आठवें वेतन आयोग में सुझाव भेजने की अवधि बढ़ी, कर्मचारियों को करना होगा इंतजार

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया में एक बार फिर समय बढ़ाया गया है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनभोगी समूहों से सुझाव एवं मांगें प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है। इससे पहले यह तिथि 30 अप्रैल निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई किया गया था।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम विस्तार होगा और इसके बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सभी सुझाव और ज्ञापन केवल आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ई-मेल अथवा मुद्रित प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

समयसीमा बढ़ने से कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगों को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। हालांकि इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि आयोग की अंतिम सिफारिशों के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। नवंबर 2025 में गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 माह का समय दिया गया है। ऐसे में आयोग की अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2027 के मध्य तक आने की संभावना जताई जा रही है।

कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएं। यदि ऐसा होता है तो वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बकाया राशि का भी लाभ मिल सकता है।

वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि कर्मचारी संगठन इस बार इसे 3 से 4 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। यदि इस मांग को मंजूरी मिलती है तो न्यूनतम मूल वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन और पेंशन से संबंधित बकाया राशि का भुगतान तो बाद में किया जा सकता है, लेकिन मकान किराया भत्ता जैसी कुछ मदों में पिछली अवधि का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी कारण कर्मचारी संगठन वेतन वृद्धि के साथ-साथ इसके प्रभावी होने की तिथि को लेकर भी चिंतित हैं।

आयोग की अंतिम सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे लाखों लोगों के आर्थिक भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है।

मासूम की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा, शव पर मिले 91 चोटों के निशान

तिरुवनंतपुरम।

केरल के नेदुमंगड़ क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आई शव परीक्षण रिपोर्ट ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मासूम के शरीर पर 91 चोटों के निशान पाए गए हैं। चिकित्सकों ने सिर और सीने पर लगी गंभीर चोटों तथा आंतरिक रक्तस्राव को मौत का कारण बताया है। जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चे की एक पसली टूटी हुई थी।

पुलिस के अनुसार मामले में गिरफ्तार सौतेले पिता आशकर के खिलाफ हत्या और बाल उत्पीड़न से संबंधित आरोप पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। अब शव परीक्षण रिपोर्ट को जांच का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। पुलिस बच्चे के हाथ में पहले हुए फ्रैक्चर की भी दोबारा जांच कर रही है।

जांच के दौरान सामने आया है कि, बच्चे की मां अखिला और आरोपी ने पहले चोटों का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया था, लेकिन पुलिस को इस दावे पर शुरू से ही संदेह था। जांच एजेंसियों का मानना है कि बच्चे के साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी मां को भी हो सकती थी। इसी आधार पर उसके खिलाफ भी साक्ष्य छिपाने और मामले में सहयोग करने से संबंधित धाराएं जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जांच अधिकारी अब पूरे घटनाक्रम और संभावित कारणों की विस्तृत पड़ताल कर रहे हैं।

इस बीच पुलिस ने आरोपी के पूर्व रिकॉर्ड और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहली पत्नी के परिजनों ने भी उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। साथ ही कुछ पुराने मामलों की भी समीक्षा की जा रही है, जिनका संबंध आरोपी से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच जारी है।

नेपाल के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध - मोदी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात के दौरान भारत और नेपाल के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है तथा भारत नेपाल के साथ अपने विशेष संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक माध्यम पर जारी संदेश में कहा कि रवि लामिछाने से चर्चा कर प्रसन्नता हुई। उन्होंने नेपाल के विकास और समृद्धि के लिए व्यक्त की गई उनकी सोच का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनस्तरीय संबंध दोनों देशों की साझेदारी की मजबूत नींव हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में नेपाल एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक साझेदार है। नई परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए भारत पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। व्यापार, ऊर्जा, संपर्क व्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

इससे पूर्व रवि लामिछाने ने अपनी भारत यात्रा के दौरान विभिन्न केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, सुरक्षा सहयोग तथा आपसी हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

लामिछाने ने इन बैठकों को सकारात्मक और उपयोगी बताते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में संवाद बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। उनकी टीम 5 जून को नेपाल लौटने वाली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार संवाद से भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्रीय सहयोग के नए अवसर विकसित होंगे।

होटल में भीषण आग, कई लोगों की मौत

नई दिल्ली।

मालवीय नगर स्थित एक होटल एवं भोजनालय में बुधवार को लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 21 पहुंच गई है बताया जा रहा है। जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। मृतकों और घायलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगाई। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भवन में स्वीकृत क्षमता से अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे। भवन से बाहर निकलने के सीमित रास्तों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि, कुछ लोग तलघर में भी ठहरे हुए थे, जिससे हादसे की गंभीरता बढ़ गई।

मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं, जो उपचार के सिलसिले में दिल्ली आए थे और उक्त होटल में ठहरे हुए थे। हादसे के बाद प्रशासन ने भवन की सुरक्षा व्यवस्था और अनुमति संबंधी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

आग लगने के कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर विद्युत शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस, दमकल विभाग और अन्य जांच एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच में जुटी हैं।

कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और मरने वालो की संख्या में वृद्धी होने की संभावना जताई जा रही है।

भीषण गर्मी में भी किसानों को लगना पड़ रहा है लाईन में, समय पर नहीं मिल रहा पैसा

माही की गूंज, बामनिया/खवासा।

आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत आने वाली बहुउद्देशी संस्था से किसानो को शून्य प्रतिशत पर लोन देने का प्रत्येक वर्ष प्रावधान है। जिससे कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। साथ ही अपनी फसल के लिए उसे शून्य प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध हो, इसी को देखते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को ऋण वितरण की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह व्यवस्था इन दिनों किसानों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। क्योंकि किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। और ऋण मिल भी रहा है तो घंटो उनको बिठाकर गर्मी में परेशान भी किया जा रहा है। बताते हैं कि, प्रतिवर्ष किसानों को ऋण मार्च के अंत में जमा करना रहता है और फिर से नए सिरे से वापस उन्हीं किसानों को ऋण देने का कार्य सस्था द्वारा किया जाता है। लेकिन जब पैसा किसान द्वारा समय पर जमा किया जाता है। तो फिर ऋण समय पर किसानों को क्यों नहीं मिल पाता है? यह प्रश्न आज भी किसानो के मन में है। जबकी पड़ोसी जिले धार मे सभी किसानो को अप्रेल और मई मे ऋण मिल जाता है। तों झाबुआ के ग्रामीण किसानो को समय पर ऋण क्यों नहीं मिल पाता है। कई किसानों का आरोप है कि हमें प्रतिवर्ष संस्था में खाता खसरा नकल के साथ ही दो-दो फोटो आदि हमसे लिए जाते हैं। जबकि सहकारी संस्थाओ में हमारा पूरा रिकॉर्ड उनके पास पहले से मौजूद है। फिर भी हमें बेवजह परेशान किया जाता है और हमें पैसों के लिए भी मुख्य शाखा में घंटो इंतजार करना पड़ता है। एक तरफ तो इतनी गर्मी है दूसरी तरफ हमें पैसों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। किसान जोरावर राठौर, भमरसिंह, हुमला, नारायण सोलंकी, भोंदरिया, आदि का कहना है कि, पैसा खाते में जमा हो गया लेकिन मुख्य शाखा में पैसे नहीं होने के कारण हमें दूसरे दिन तो कभी घंटो इंतजार करना पड़ रहा है। वही कई किसानों का तो दूसरे दिन नंबर लग रहा है। बताते हैं, कि सारंगी, भामल, करडावद, खवासा आदि किसान जिला सहकारिता केंद्रीय बैंक झाबुआ की शाखा बामनिया में कई किसानों को पैसों के लिए घंटो लाइन में लगना पड़ रहा है। तो जहां बैंक पर पैसे वितरण किए जाते हैं वहां किसानों के लिए कोई छायादार बैठने के लिए व्यवस्था तक नहीं है साथ ही पीने के लिए पानी भी नहीं है।

खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसान, इस बार अच्छी बारिश व फसल होने का अनुमान

माही की गूंज, बरवेट।

जिले के किसानों ने खरीफ सीजन को लेकर तैयारी शुरु कर दी है। किसान खेतों में हकाई जुताई करने के साथ साथ देसी खाद डालने के काम मे लग गए है। क्षेत्र में हुई प्री मानसून की बरसात के बाद खेतों में किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है। खरीफ फसल की तैयारी में किसान जुट गए है। किसान इस बार अच्छी बारिश की कामना साथ साथ अच्छी फसल होने का अनुमान लगा रहे है। लिहाजा मानसून आगमन के पहले कृषि विभाग ने भी अपने स्तर पर खरीफ फसल की लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इस बार जिले के 1 लाख 89 हजार 260 हेक्टेयर में खरीब की विभिन्न फसलें ली जाएगी। इस बार कुछ फसलों की बोआई का रकबा घट बढ़ सकता है। वहीं कुछ फसल को इस बार लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया। कृषि विभाग का कहना है कि कई फसल ऐसी है, जो यहां के किसान लगाते ही नहीं है, इस वजह से लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया। इस साल भी कृषि विभाग गत वर्ष के आधार पर ही खरीफ का लक्ष्य निर्धारण किया है। वर्तमान में रबी फसल के तहत कृषि कार्य की शुरुआत हो गई है। यहां के किसान सोयाबीन की फसल को ज्यादा महत्व देते है। अबकी बार सोयाबीन का रकबा 68 हजार 250 हेक्टेयर के लगभग प्रस्तावित लक्ष्य है। जो की पिछले साल से 6:कम है। गत वर्ष सोयाबीन के रकबा 72 हजार 540 हेक्टेयर था। रबी फसल से निपटने के बाद अधिकांश किसान अब खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए है। कुछ ही किसान गर्मी की फसल लेने के तहत कृषि कार्य निपटाने के बाद खरीफ फसल की तैयारी में जुटेंगे। जिले के किसान सोयाबीन की फसल को ज्यादा महत्व देते है। इस वजह से सोयाबीन का रकबा ही इस बार ज्यादा है।

जुगाड़ू खाली ट्रक में से पुलिस ने की अवैध शराब जप्त

माही की गूंज, थांदला।

ये भारत है और यहां जुगाड़ू व्यवस्था करने में हर कोई अपने-अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते नजर आता है। शराब माफियाओं की बात करें तो यह माफिया नए नित जुगाड़ कर शराब का परिवहन करते हैं। हमने कई ऐसी शराब जप्ती के मामले देखे हैं जिसके तहत ट्रकों में विभिन्न प्रकार के जुगाड़ के साथ कवरिंग में अवैध शराब ढोते हुए मुखबिर की सूचना पर बाहरी शराब माफियाओं की अवैध शराब आबकारी व पुलिस ने जप्त की है।

ईसी कड़ी में 30-31 मई की रात्रि में थांदला पुलिस ने ऐसी जुगाड़ू ट्रक जो की पूरी तरह से खाली थी पर इस खाली जुगाड़ू ट्रक में 111 पेटी विदेशी अवैध शराब की पेटियां जप्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि, राजस्थान, कुशलगढ़ होते हुए टिमरवानी से परवलिया होते हुए गुजरात की ओर जाने वाली एक ट्रक में अवैध शराब ढोई जा रही है। थांदला पुलिस ने मुखबीर की सूचना के आधार पर टिमरवानी से परवलिया मार्ग पर आईसर ट्रक को रोका। जिसमे डाला खोलने पर पूरी ट्रक अंदर से खाली थी। लेकिन ट्रक के ऊपरी हिस्से में त्रिपाल ढकी थी। उसी त्रिपाल की आड़ में ट्रक के छत की ओर प्लाय का एक ढांचा बना दिखा। तथा उक्त बने जुगाड़ी ढांचे पर जब पुलिस ने देखा तो वहां विभिन्न प्रकार की 111 पेटी विदेशी शराब जप्त की।

उक्त शराब जप्ती के साथ यह सामने आया कि, शराब माफिया अपने क्षेत्र में कई तरह के जुगाड़ लगाकर अवैध शराब का परिवहन कर पुलिस व आबकारी विभाग को चकमा दे रहे हैं।

पुलिस ने शराब के साथ 30 लाख से अधिक का मशरूका जप्त कर चालक सुरेश कुमार छगन राम निवासी रामसरिया बायडू जिला बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया।

किरायेदारों एवं बाहरी व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, रिसोर्ट एवं किराए पर दी जाने वाली संपत्तियों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने

महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। झाबुआ की भौगोलिक स्थिति गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से लगी होने के कारण यहां बाहरी व्यक्तियों का आवागमन अधिक रहता है, जिससे पुलिस जांच के दौरान उनकी सही जानकारी उपलब्ध न होने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिले की शांति, लोकशांति, जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था पर संभावित खतरा उत्पन्न होता है।

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि, मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों को बिना सूचना दिए रखने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) एवं (2) के अंतर्गत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार किरायेदारों को रखने से पूर्व मकान एवं दुकान मालिकों को संबंधित थाने में विहित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य होगा, साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान-पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखनी होंगी। घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों के मामले में भी मालिकों को उन्हें नियुक्त करने से पूर्व थाने में सूचना देना और उनके पहचान-पत्र की प्रति रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार होटल, लॉज एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले सभी व्यक्तियों से पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाना होगा तथा उनकी सूची प्रत्येक माह थाने को प्रेषित करना होगी।

ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और कूरियर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को अपने उन कर्मचारियों की जानकारी थाने में उपलब्ध करानी होगी जो घर-घर जाकर वितरण करते हैं। साथ ही उनके पहचान-पत्र की प्रतियां भी रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को अपने स्तर पर अथवा एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए सुरक्षा गार्डों की जानकारी भी विहित प्रारूप में थाने को उपलब्ध करानी होगी और उनके पहचान-पत्र की प्रति रखना आवश्यक होगा।

आयोजित होगा ऑनलाइन योग सत्र

माही की गूंज, झाबुआ।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाबिल्ड हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 14 जून 2026 को प्रातः सवा 6 से 7.35 बजे तक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जाएगा।

इस योग सत्र में सहभागिता के लिए इच्छुक नागरिक टोल फ्री नंबर 18003157008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

समस्त विभागों, शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि, वे अपने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन को अधिक से अधिक संख्या में इस योग सत्र से जुड़ने हेतु प्रेरित करें, ताकि योग के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिकाधिक लोग इसके लाभ प्राप्त कर सकें।

पूर्व जज गिरिबाला सिंह अब कैदी नंबर 71...

भोपाल। ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल की अदालत ने पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को दोनों को भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया। जेल सूत्रों के मुताबिक, गिरिबाला सिंह को महिला मेडिकल सेक्शन में रखा गया है। यहां उनकी पहचान अब कैदी नंबर 71 होगी। वहीं समर्थ सिंह को जेल की बैरक नंबर-4 में रखा गया है, जहां उनकी पहचान कैदी नंबर 1782 के रूप में होगी।

जेल मैन्युअल के मुताबिक, दोनों को दैनिक उपयोग का सामान उपलब्ध कराया गया है। इनमें थाली, कटोरी और चादर जैसी जरूरी वस्तुएं शामिल हैं। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो 63 साल की गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में अपने पक्ष की पैरवी खुद की। सुनवाई के दौरान उनकी और ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश हुए वकील अनुराग श्रीवास्तव के बीच तीखी बहस हो गई।

गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ सिंह के साथ धक्कामुक्की और हाथापाई की गई थी। इस पर अनुराग श्रीवास्तव ने जवाब देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो कोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

सुनवाई के दौरान ट्विशा के परिवार की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि समर्थ सिंह को जबलपुर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चेंबर में शरण कैसे मिली। समर्थ सिंह की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होता है तो उसे सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का अधिकार है।

आखिर कौन थीं ट्विशा शर्मा?

33 वर्षीय ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं। उन्होंने एमबीए किया था और दिल्ली में मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशन सेक्टर में काम किया था। वे मॉडलिंग से भी जुड़ी रही थीं। ट्विशा श्मिस पुणेश् का खिताब जीत चुकी थीं और एक तेलुगु फिल्म में भी काम कर चुकी थीं। दिसंबर 2025 में उनकी शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने भोपाल स्थित ससुराल में मृत पाई गई थीं। शुरुआती जानकारी में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था। कहा गया कि वे फंदे से लटकी मिली थीं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि, ट्विशा के परिवार ने मौत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। परिवार का आरोप है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता था। वहीं जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया है कि कुछ डिजिटल साक्ष्यों और चौट रिकॉर्ड्स से ऐसे संकेत मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सामान्य प्रसव से तीन बेटियों का जन्म, मां एवं नवजात स्वस्थ

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला चिकित्सालय में एक दुर्लभ एवं सुखद घटना के तहत एक महिला ने सामान्य प्रसव के माध्यम से तीन स्वस्थ बेटियों को जन्म दिया। वर्तमान में माता एवं तीनों नवजात शिशुओं की स्थिति स्वस्थ है।

जानकारी के अनुसार, श्रीमती रीना पति सुकराम, निवासी कुशलपुरा जिला धार मायका गोपालपुरा, जिला झाबुआ को प्रसव पीड़ा होने पर जिला चिकित्सालय झाबुआ में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में सफलतापूर्वक सामान्य प्रसव कराया गया।

जन्मी तीनों नवजात बेटियों का वजन क्रमशः 1.2 किलोग्राम, 1.3 किलोग्राम एवं 1.8 किलोग्राम है। कम वजन होने के कारण प्रथम एवं द्वितीय नवजात को विशेष निगरानी एवं उपचार के लिए एनआईसीयू में रखा गया है। जबकि 1.8 किलोग्राम वजन वाली नवजात अपनी माता के साथ स्वस्थ है। चिकित्सकों के अनुसार माता एवं तीनों नवजातों का स्वास्थ्य निरंतर बेहतर है।

जिला चिकित्सालय झाबुआ परिवार ने तीनों नवजात बेटियों एवं उनकी माता के उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

कलेक्टर ने कई जगहो का किया निरीक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ट्रेंचिंग ग्राउंड, डॉ. भीमराव अंबेडकर गार्डन तथा वाटर फिल्टर प्लांट किशनपुरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचकर नगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर के 18 वार्डों से एकत्रित होने वाले कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण किया जाए। कलेक्टर ने विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक उपकरण एवं टूल्स क्रय कर कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए।

इसके पश्चात कलेक्टर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गार्डन के सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव में लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गार्डन की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने, नियमित साफ-सफाई बनाए रखने तथा परिसर की सुंदरता एवं उपयोगिता बढ़ाने के निर्देश दिए।

वाटर फिल्टर प्लांट किशनपुरी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पेयजल की गुणवत्ता की जांच हेतु क्लोरीन टेस्ट करवाया तथा जल शोधन प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को शहर की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाने तथा पेयजल आपूर्ति को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।

कांग्रेस की राज्यसभा सीट पर मंथन तेज

भोपाल।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस के हिस्से में आने वाली एक सीट को लेकर पार्टी में मंथन तेज हो गया है। नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। अंतिम निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाना है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व अभी विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक पहलुओं पर विचार कर रहा है। इसी कारण अंतिम घोषणा तक कई नाम चर्चा में बने हुए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सार्वजनिक रूप से राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके नाम को लेकर चर्चाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की इच्छा होने पर स्थिति में बदलाव संभव है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि उन्होंने स्वयं कई बार इस दौड़ से बाहर होने की बात कही है, लेकिन संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और नेतृत्व से निकटता को देखते हुए राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं।

पार्टी केवल वरिष्ठता के आधार पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर भी निर्णय लेने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेताओं के नाम भी चर्चाओं में बताए जा रहे हैं।

कांग्रेस नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का भी आकलन कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा उम्मीदवार का चयन केवल एक सीट का मामला नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार अगले एक-दो दिनों में उम्मीदवार के नाम पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। तब तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और समर्थक नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

सूखे कंठ, डूबती जिंदगी, जिले में पेयजल संकट को समझने को तैयार नहीं जिला प्रशासन

पानी के लिए आंदोलन करता आमजन, फिसड्डी साबित होती सरकार की योजनाएं

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में पेयजल संकट कोई नई बात नहीं है। प्रदेश में सरकारें, जिले में अधिकारी आते -जाते रहते है, लेकिन जिले की पेयजल समस्या का समाधान अधिकारियों की बदौलत सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही नजर आता दिखाई पड़ता है। ना नेता न जनप्रतिनिधि दशकों से इस समस्या के समाधान तक नही पहुंच पाए। जबकि हर बार वे चुनाव के दौरान जनता से इन्ही सब समस्याओं के वादे करते आए है। हालात यह है कि, देश की आजादी को 8 दशक पूर्ण होने को है और जिले में अब भी आमजन पेयजल संकट से दो चार हो रहे है। प्यास बुझाने सूखे कंठ कहीं डूबने से मौत का शिकार हो रहे है तो कहीं जान जोखिम में डाल कंठ की प्यास बुझा रहे है। मगर इन सबके बीच ना तो जिला प्रशासन को इनकी परवाह है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि को और ना ही किसी सरकार को। तो फिर पेयजल की जद्दो जहद में होने वाली मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है...? सरकारी आंकड़े बताते है कि, जिले के 799 गांवों में पेयजल योजनाएं सुचारू रूप से काम कर रही है। इन योजनाओं में काम पूरा कर उन्हे पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन जिले की हकीकत कुछ और ही है। यहां अब भी लोग पेयजल की तलाश में अपनी जाने गवां रहे है।

मंगलवार को जिले के कल्याणपुरा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा में एक ऐसी ही भयावह तस्वीर सामने आई है। जिसमें कुप से पानी भरने गई 12 वर्षिय बालिका की पैर फिसलने से डूबने के चलते मौत हो गई। गोपालपुरा गांव की 12 वर्षिय बालिका शिवानी पिता बिजिया मकवाना पेयजल लेने के लिए बिना मुंडेर के 20 फीट गहरे कुप पर गई थी कि, अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे कुप के अंदर जा गिरी। साथ गई छोटी बहन यह घटना देखकर घबरा गई और मदद लेने के लिए परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंची। इस दौरान शिवानी कुप के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी।

परिजन घटना स्थल पर पहुंचे, इस उम्मीद में कि शिवानी जिंदा बच जाएगी। लेकिन समय बीतता रहा और उम्मीदें टूटती रही। परिजनों और ग्रामीणों ने 112 पर सूचना दी मदद पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन कुप का पानी निकालते-निकालते लगभग तीन घंटे बीत गए। जिसके बाद शिवानी का शव दिखाई दिया। कल्याणपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। जिसके बाद शिवानी का अंतिम संस्कार हो सका।

मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे शिवानी अपनी बहन के साथ गांव के ही एक कुप पर पानी भरने गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो जिस कुप पर ये दोनों बहने पानी भरने गई थी वह कुंआ उपर से बहुत ही चौड़ा है। कुप के आसपास कोई मुंडेर नहीं है। पानी भरने के लिए कुप के अंदर 20 फीट तक खड़ी ढलान पर उतरना पड़ता है इसी ढलान पर उतरते समय शिवानी का पैर फिसला और वह कुप के गहरे पानी में जा गिरी। परिजनों के अनुसार गांव के कई परिवार इसी कुप से पानी भरते है। शिवानी भी रोज इसी कुप पर पानी भरने जाती थी। कुप की परिस्थिति से पूरा गांव वाकिफ है लेकिन बावजूद इसके पानी के लिए गांव के सभी लोग यह खतरा मौल लेते है।

यह पूरी घटना बड़ी ही हृदय विदारक है। किस तरह जिले में महज पीने के पानी के लिए एक मासूम की जान चली जाती है और परिजन बिलखते रह जाते है। यह जिले का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि, ऐसे हादसे हर साल लगातार होते ही रहते है। जिले के ग्रामीणों की पेयजल आपुर्ति की कीमत मानों उनकी जानें ही है। पेयजल के लिए होने वाली ऐसी घटनाओं और मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है...? विकास का ढिंढोरा पीटने वाले राजनीतिक दल, जिले में प्रशासनिक तंत्र में बैठे आला अधिकारी, पेयजल के लिए काम करने वाला विभाग सब मिलकर आजादी के इतने समय बाद भी जिले की पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त नहीं कर सके या करवा सके। क्या यह इस जिले के ग्रामीणों का हक नहीं है कि, उन्हे बिना जोखिम साफ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके...? या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि, पूरे जिले में ऐसे कई गांव है जहां पेयजल संकट है, इसी तरह के खुली मुंडेर के कुप है, जो ग्रामीणों और मासूमों की मौत का कारण बन रहे है या बनने को तैयार है। कहीं पूरे जिले की यही हकीकत तो नहीं है...? क्योंकि वर्तमान में हर सप्ताह जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों में सबसे ज्यादा संख्या पेयजल संकट के आवेदनों की ही है।

यह घटना प्रशासन के उन दावों की पोल भी खोल रही है जिसमें प्रशासनिक जिम्मेदार यह दावा करते है कि, जिले में 799 गांवों में पेयजल योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मगर जमीनी हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। जिन योजनाओं की बात सरकार के जिम्मेदार अधिकारी कर रहे है, उसके लिए कई गांवों में तो जल स्त्रोत ही नहीं है। भीषण गर्मी में गांव के वे जल स्त्रोत जो हर घर जल हर घर नल पेयजल योजना का आधार थे पूरी तरह से सूख चुके है। जिले के कई गांवों में पानी की टंकिया खड़ी तो है मगर वे खुद भी प्यासी है। ग्रामीणों के आंगन में नल तो है लेकिन उनकी टोटियां भी सूखी पड़ी है। इस स्थिति में ग्रामीणों के पास बचते है तो सिर्फ और सिर्फ जान लेवा कुप। इन खतरनाक कुप में ग्रामीण अपनी व परिवार की प्यास बुझाने जान हथेली पर लेकर उतरने को मजबूर है।

तो फिर ऐसी पेयजल योजनाओं का क्या मतलब जो धरातल से कोसो दूर है और ग्रामीणों की जान सरकार के सारे प्रयासों के बाद भी इस आधुनिकता के दौर में हथेली पर है। जिले में तंत्र में बैठे अधिकारी कभी अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे...? या फिर हथेली में दिल्ली और अंगूठे को कुतुब मीनार ही बताते रहेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह की पेयजल को लेकर होने वाली मौतों का जिम्मेदार जिला प्रशासन और तंत्र में बैठे निठल्ले अधिकारी ही है।

मजदूर पलायन पर, क्योंकि की जेसीबी जिंदाबाद

रात के अंधेरे में मजदूर के हक पर चला दी जेसीबी, रोका तो मिली धमकी

माही की गूंज, पेटलावद।

एक बार फिर मजदूरो के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। जहां एक ओर ग्रामीण वर्ग स्थानीय स्तर पर कोई कार्य नहीं होने से बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए पलायन कर जाते है वही मजदूरो को रोजगार देने के नाम पर एजेंसी केवल कागज रंगीन कर वाहवाही रिकॉड दिखा कर लूट रहे है। यहां विकास खंड की ग्राम पंचायत हनुमंतिया में मजदूरों से बनवाया जाने वाला तालाब जेसीबी से बनवाने जाने का मामला सामने आया है । ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर ग्रामीणों ने मजदूरों को काम नहीं देने का आरोप लगाया है।

क्षेत्र के जनपद सदस्य मुकेश भाभर ने मामले की जानकारी जनपद पंचायत सीईओ को भेज कर कार्रवाई की मांग की है। जनपद सदस्य मुकेश भाभर ने बताया कि, ग्राम पंचायत हनुमंतिया में सरपंच-सचिव द्वारा मनमानी से रात में चल रही जेसीबी से तालाब निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ओर ग्रामीणों ने जा कर रोका तो पत्थर व लाठी से हमला किया गया। लोग काम के लिए पलायन पर जा रहे है ओर सरपंच-सचिव मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे है। मुकेश भाभर ने बताया कि, मजदूर सुबह मजदूरी के लिए गए तो उनको। ग्राम पंचायत ने ये कह कर रवाना कर दिया कि, अभी जनपद से मस्टर जारी नहीं हो रहे इसलिए तालाब का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा और रात में ही जेसीबी बुलवा के तालाब की पडल खोदने का कार्य किया गया।

पूर्व में भी बारिश में बह चुका है तालाब

हनुमंतिया ग्राम पंचायत में ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पूर्व भी ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए तालाब बारिश में घटिया निर्माण की वजह से बह चुके हैं। जनपद सदस्य मुकेश भाभर ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

जहा सत्संग, सेवा, सम्मान और स्मरण है वह घर स्वर्ग समान - पंडित त्रिवेदी

माही की गूंज, रायपुरिया।

ग्राम के झाबुआ रोड स्थित हनुमान धाम मन्दिर के समीप नौ दिवसीय श्रीराम कथा का समापन हुआ। नौवें दिन श्रीराम कथा में भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक का मंचन किया गया। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रभु श्रीराम की आरती उतारी गई। कथावाचक श्याम सुंदर त्रिवेदी ने कहा कि, जब खरदूषण के वध होने की बात सूर्णपंखा ने रावण को सुनाई तो रावण समझ गया भगवान का अवतार हो गया। तामस देह से भक्ति नहीं होगी, तो मुक्ति के लिए उसने भगवान राम से बैर की युक्ति सोची। मतलब राक्षस प्रवृति के लोग कभी भक्ति करके मुक्ति नहीं पा सकते, इसीलिए भगवान से शत्रुता करके उनके हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उसने भगवान श्री राम से बैर लिया ताकि मोक्ष मिल सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम स्वयं कहते हैं, जब लोक पर कोई विपत्ति आती है तब वह रक्षा पाने के लिए मेरी प्रार्थना करता है, परंतु जब मुझ पर कोई विप्पति या संकट आता है तब मैं उसके निवारण के लिए पवनपुत्र हनुमान को याद करता हूं। सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान श्री राम ने सत्य को स्थापित करने के लिए रावण का वध किया। भगवान श्रीराम की कथा हमारे चरित्र चिंतन को बदलने वाली है। यदि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला पाए तो श्रीराम कथा सुनने का और सुनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । जहा सत्संग, सेवा, सम्मान और स्मरण है वह घर स्वर्ग समान होता है। आयोजन परिवार द्वारा कथा वाचक पंडित श्याम सुंदर त्रिवेदी का शाल, श्रीफल, साफा बांधकर सम्मान किया। इसके बाद आरती उतारकर प्रसादी वितरित की।

हाट बाजार हुआ मंडी में स्थानांतरित

माही की गूंज, थांदला।

नगर के हाट बाजार को व्यवस्थित रूप से संचालित किए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर प्रशासन ने पहल करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भास्कर गाचले के निर्देश पर नगर पालिका एवं प्रशासनिक अमले द्वारा पुरानी सब्जी मंडी परिसर में हाट बाजार को सुव्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई।

मंगलवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हाट बाजार में आने वाले व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की तथा बाजार संचालन को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के प्रयास किए। लंबे समय से बाजार की अव्यवस्थित स्थिति के कारण व्यापारियों एवं नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके निराकरण की मांग लगातार उठ रही थी।

एसडीएम भास्कर गाचले ने बताया कि, हाट बाजार की व्यवस्था को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वर्तमान कार्रवाई इस दिशा में प्रारंभिक कदम है। बाजार का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यक सुधारों का आकलन किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने के लिए नगर पालिका को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि हाट बाजार ऐसा स्वरूप ग्रहण करे जिससे व्यापारियों को बेहतर वातावरण मिले और नागरिकों को भी सुगमता से खरीदारी की सुविधा उपलब्ध हो।

प्रशासन की इस पहल का नगरवासियों ने स्वागत करते हुए एसडीएम भास्कर गाचले का आभार माना।

ट्रक और तूफान जीप की भिडंत

माही की गूंज, करवड़।

करवड़-सारंगी मार्ग पर सोमवार को एक ट्रक और तूफान जीप की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में तूफान वाहन चालक सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। हादसा करवड़ से करीब एक किलोमीटर दूर सारंगी रोड पर दोपहर को हुआ। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में शांतिलाल भाबर और कैलाश पारगी घायल हुए। सूचना मिलते ही करवड़ चौकी पुलिस एवं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर काफी जोरदार थी जिससे दोनों वाहनों में नुकसान हुआ।

नेताओ ने रोड स्वीकृत करवाने के नाम पर मीडिया, सोशल मीडिया पर खूब लूटी वाहवाही, काम आज तक शुरू नहीं

पूरी तरह जर्जर हो चुके मार्ग पर चलने वाले परेशान, नेता नगरी के पास जवाब नहीं

माही की गूंज, बरवेट/पेटलावद। जगदीश प्रजापत

रायपुरिया-बरवेट-करवड़ 25 किमी टू लाइन मार्ग निर्माण का हैं को लेकर टेंडर ओपन हो चुका है। रोड निर्माण का कार्य प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद शुरू हो जायेगा। विभाग से मिली जानकारी अनुसार रायपुरिया करवड़ मार्ग 25 किमी के टेंडर खुल गए हैं। इंदौर की केजी गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से टेंडर खुला है, जो स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी। 52 करोड़ रुपए की लागत से टू लाइन का निर्माण होगा। अभी मार्ग सिंगल पट्टी है और जगह-जगह गड्?ढे हो गए हैं। मजबूरी में लोगों को जर्जर मार्ग से आवाजाही करना पड़ रही है। इस मार्ग का चौड़ीकरण होने से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

रोजाना निकलते हैं हजारों वाहन

25 किमी लंबे जर्जर हो चुके मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। गुजरात राज्य से विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग जाने के लिए एक यही शार्ट कट मार्ग है। वही मालवा क्षेत्र रतलाम-बड़नगर के श्रद्धालु विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते है। पूरे मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे व खस्ताहाल सड़क के चलते इस मार्ग को पार करने में लगभग दो गुना समय समय लगता है। साथ ही वाहन चालक को परेशान भी होना पड़ता है।

मार्ग को लेकर टेंडर ओपन होने से क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है। टेंडर ओपन होने के बाद भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ हो जायेगा। बीते एक वर्ष से मार्ग के निर्माण को लेकर क्षेत्र के नेता लगातार वाहवाही लूटते नजर आ रहे है लेकिन मार्ग निर्माण शुरू में हुई देरी के चलते नेताओं ने भी मोन धारण कर लिया।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति थांदला जिला झाबुआ (म.प्र.)

email - mandithandla@gmail.com

कमांक/मण्डी/निर्माण/2026-27/86 थांदला, दिनांक 21.05.2026

// बी.ओ.टी. तोलकांटा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना //

कृषि उपज मंडी समिति थांदला द्वारा ई-टेंडर प्रणाली के माध्यम से उपमंडी प्रागंण खवासा मे स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांन्सफर बी.ओ.टी. आधार पर 10 मे.टन क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तोलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम कमांक 2026_MPSAM_509626_1 द्वारा ऑनलाइन निविदां दिनांक 16.06.2026 को समय शाम 06:00 च्ड तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(एस.एल. पंवार) सचिव

(भास्कर गाचले) भारसाधक अधिकारी

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में सामूहिक प्रयास मददगार

निसंदेह, नशे का निरंतर फैलता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है। संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गठजोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें। लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस अभियान का सुखद पहलू यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते-ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है। कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा। लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है। सही मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।

वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है। कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है। कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है। निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं। जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की समाज में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं। चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है। जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे की डोज जुटाने के लिये कुछ छात्र व युवा अपराध की राहों में फिसल जाते हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि नियमित रूप से नशा तस्करों और ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी करके तुरंत सजा दी जाए। वहीं दूसरी ओर नशे की खरीद-फरोख्त में संलिप्तता पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने, पासपोर्ट निरस्त करने से भी जहरीले कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। साथ ही सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों में, जहां सीमा पार से नशे की तस्करी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिये की जा रही है, वहां अतिरिक्त सावधानी की भी जरूरत है। नशा तस्करों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सजा देना, इस अभियान में मददगार साबित होगा।

भारतीय भूमि अतिक्रमण मुद्दे पर घिरे बालेन्द्र

गत 27 मार्च को पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक बार भी संघीय संसद को संबोधित नहीं किया थाकृयहां तक कि अनिवार्य साप्ताहिक प्रश्न-उत्तर सत्रों के दौरान भी नहीं। उनकी चुप्पी तोड़ने और विधायिका के प्रति जवाबदेही दिखाने का दबाव उन पर लगातार बढ़ रहा था। और फिर रविवार को जब बालेन्द्र शाह संसद में बोले, सभी सन्नाटे में आ चुके थे। उन्होंने अपने आलोचकों को शांत करने के बजाय, मानो डंक मारने वाली मधुमक्खियों का एक झुंड ही छोड़ दिया। जिसे अंग्रेजी में 'पैंडोरा बॉक्स खोलना' कहते हैं।

संसद में दो अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए, शाह ने सबसे पहले कहा कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ प्रयास जारी हैं। लेकिन, फिर उन्होंने यह भी जोड़ा कि न केवल भारत ने नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि भारत के साथ मौजूदा सीमा विवादों में से कई की जड़ें 1816 में ब्रिटिश भारत के साथ हुई सुगौली संधि में हैं, इसलिए उनकी सरकार भारत-नेपाल सीमा चर्चाओं में ब्रिटिश पक्ष को शामिल करने की कोशिश कर रही है।

काठमांडू पोस्ट जैसा अखबार भी इस बयान से हैरान था। अगले दिन के सम्पादकीय में अखबार लिखता हैकृ 'सीमा विशेषज्ञों के साथ-साथ उन वरिष्ठ पूर्व सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है, ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसमें भारत ने कभी 'नेपाली अतिक्रमण' का मुद्दा उठाया हो। इसलिए, प्रधानमंत्री का यह बयान भविष्य की सीमा वार्ता में भारत के पक्ष को मजबूत करता है।'

कोई राष्ट्रीय अखबार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करे, तो यह उभयपक्षीय हितों के लिए अच्छा नहीं है। भारत से यदि भूमि विवाद नहीं होता, तो 'बाउंडरी वर्किंग ग्रुप' का गठन क्यों किया गया? संयुक्त तकनीकी समिति ने लगभग 26 वर्षों तक कार्य किया। यह दावा किया गया कि सीमा संबंधी 97 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर लिया गया। शेष तीन प्रतिशत का समाधान करना उनकी क्षमता से परे था। उसमें कालापानी-लिम्पियाधुरा शामिल हैकृजो 370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा अतिक्रमण हैय इसके अलावा 24 किलोमीटर का सुस्ता क्षेत्र और लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले अन्य स्थान भी इसमें हैं। कुल मिलाकर, ऐसे लगभग 71 स्थान हैं जो 606 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल घेरते हैं। इस स्थिति के बने रहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक, सीमांकन के लिए पुराने मानचित्रों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता है।

काश! काठमांडू पोस्ट ने बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की पुस्तक 'द नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड द शिफ्टिंग बॉर्डर्स ऑफ नेपाल' में बर्नार्डो माइकल द्वारा की गई टिप्पणी पर गौर किया होता, 'आज भी, भारत और नेपाल

के बीच सीमा विवादों की उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आधुनिक सीमाओं के निर्धारण की यह परियोजना सदैव एक 'अधूरी परियोजना' ही बनी रहेगी।'

नेपाल के लिए मुश्किल यह है कि लिपुलेख के मुद्दे पर चीन उसके साथ नहीं खड़ा है। लिपुलेख-लिम्पियाधुरा ट्राइजंक्शन भारत का है, उसकी पुष्टि 15 मई, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ व्यापार समझौता है। यह भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था, जिस पर चीनी प्रधानमंत्री ली कछियांग के साथ पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें औपचारिक रूप से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार पर सहमति बनी थी। 41-सूत्री संयुक्त बयान के बिंदु 28 में लिपुलेख दर्रे (कियांगला) को औपचारिक रूप से एक द्विपक्षीय सीमा व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग के रूप में मान्यता दी गई थी।

तब नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि भारत और चीन ने उसकी सहमति के बिना, उसके दावे वाले क्षेत्र से होकर व्यापार करने पर बातचीत की है। बाद के दिनों में नेपाल के तीन प्रधानमंत्रियों केपी शर्मा ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा ने लिपुलेख-लिम्पियाधुरा के बॉल को जमकर खेला। बालेन्द्र शाह से पहले पीएम ओली इस मुद्दे को उठाने 3 सितम्बर, 2025 को पेइचिंग में आहूत थिएनमान चौक विजय दिवस समारोह तक गए लेकिन, चीनी सत्ता प्रतिष्ठान ने उसे अनसुना कर दिया। चीन और भारत तय कर चुके थे कि लिपुलेख-लिम्पियाधुरा ट्राइजंक्शन के बरास्ते जून, 2026 में उभयपक्षीय व्यापार होना है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब तक नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी कब्जा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन-किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है। कई सांसद यह चाह रहे हैं कि संसद के रिकार्ड से यह बयान स्पन्ज किया जाये। लेकिन, जुबान से निकली बात और कमान से छूटे तीर की वापसी नहीं हो सकती।

पुष्परंजन

नेपाली मीडिया भी हतप्रभ है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट प्रधानमंत्री शाह के बयान को अपरिपक्व मानते हुए लिखता है, 'अगर उन्होंने 'अतिक्रमण' शब्द के बजाय 'सीमा-पार के कब्जे' शब्द का इस्तेमाल किया होता, तो कोई विवाद नहीं होता। दूसरा, नेपाल और भारत के बीच उभयपक्षीय मामले में ब्रिटेन को शामिल करने की इच्छा भी गलत है। भारत ने बार-बार कहा है कि वह बाउंडरी बातचीत में किसी तीसरे पक्ष को कभी नहीं कबूल करेगा, चाहे वह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल के साथ हो।'

जो भी हो, बालेन्द्र शाह का यह बयान भारत-नेपाल संबंधों का कड़वा सच है, जिसे वहां के तथाकथित राष्ट्रवादी नेता और प्रतिक्रियावादी पचा नहीं पा रहे हैं। काठमांडू स्थित सिंह दरबार के गर्भ में वो तमाम दस्तावेज गर्क हैं, जिसमें भूमिहरण संबंधी नक्शा और दस्तावेजों की हेराफेरी नेपाली नौकरशाहों ने समय-समय पर की है। नेपाली नेताओं की बौखलाहट की वजहें हैं। नेपाली संसद के निचले सदन में 13 जून, 2020 को लिपुलेख ट्राइजैक्शन की दावेदारी को सही ठहराने के लिए एक फर्जी चूचे नक्शा पास किया गया था। उसके सोर्स पर तत्कालीन सांसद सरिता गिरि ने सवाल किया, तो उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई।

नेपाल की लीडरशिप जिस 10 सूत्री सुगौली संधि को जपती रहती है, कम से कम उसके तीसरे और पांचवें बिंदु को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पांचवें बिंदू में लिखा हैकृ 'नेपाल के राजा, उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी दावों का परित्याग करेंगे।' भूलवश या अपरिपक्वता कहें, बालेन्द्र शाह ने जिस विवादित जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है, उसे वापस बोतल में डालना अब मुश्किल होगा।

रिजर्व बैंक ने खोली अर्थव्यवस्था के ढोल की पोल

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े विभिन्न संकेतक यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है? पिछले कुछ वर्षों में सरकार और उसके समर्थकों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया जा रहा था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाई देने वाली वास्तविकताएं एक अलग कहानी कह रही हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है। एक समय देश अपनी जरूरत का लगभग 18 प्रतिशत कच्चा तेल और गैस स्वयं उत्पादित कर लेता था। शेष 82 प्रतिशत आयात करना पड़ता था। अब आयात पर निर्भरता और बढ़ गई है। कच्चे तेल, गैस, उर्वरक और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक सामान और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच बढ़ता असंतुलन चिंता का विषय है। यदि किसी देश का आयात लगातार निर्यात से अधिक रहेगा तो अंततः विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। भारत का व्यापार घाटा साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में वृद्धि दिखाई नहीं दे रही। जिस गति से आयात बढ़ा है, उस अनुपात में निर्यात नहीं बढ़ पाया है। इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ रहा है। डॉलर और युआन जैसी मुद्राओं के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। जिसके कारण आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। पिछले वर्षों में सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए, आलोचकों का मानना है, इन अभियानों का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में कहीं पर दिखाई भी दिए तो वो भी बहुत नीचे स्तर पर हैं। भारत में उत्पादन बढ़ाने के बजाय आयात आधारित उपभोग अर्थव्यवस्था को सरकारी

नीतियों से बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता का एक दूसरा कारण देश में बढ़ता कर्ज है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार उधार लेकर खर्च बढ़ा रही हैं। निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। गोल्ड लोन, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड आधारित उधारी में तेजी से वृद्धि हुई है। जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास का आधार उत्पादन और आय की बजाय कर्ज बनने लगे, तो यह स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं मानी जाती। जब खर्च करने के लिये पैसे नहीं होंगे, तो आर्थिक विकास कैसे संभव है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा आवश्यक है। इन तीनों घटनाओं ने छोटे और मध्यम उद्योगों को गहरा झटका दिया। असंगठित क्षेत्र, जो भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था, आज भी वह उबर नहीं पाया है। बेरोजगारी और महंगाई ने आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। लोगों की आय कई वर्षों से सीमित है। आय की तुलना में अधिक तेजी से जीवन-यापन का खर्च बढ़ रहा है।

शेयर बाजार को लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बताया जाता रहा। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निकासी की जा रही हैं। यदि विदेशी निवेश कम होता है, घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता, तो आर्थिक विकास की रफ्तार पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर एशिया के कई शेयर बाजार अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल रही है। ऊर्जा आयात महंगा होता है, तो उसका असर परिवहन, कृषि, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पड़ता है। अंततः इसका भार आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। वर्तमान स्थिति की तुलना 1991 के आर्थिक संकट से होने लगी है। भारत के पास उस समय की तुलना में वर्तमान में कहीं अधिक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और विकसित वित्तीय बाजार मौजूद हैं। यह आशंका इस लिये व्यक्त की जा रही है, उस समय की तुलना में कर्ज और ब्याज का बोझ ज्यादा है।

सनत जैन

बढ़ता व्यापार घाटा, रोजगार संकट, महंगाई, सार्वजनिक ऋण और आयात पर बढ़ती निर्भरता ऐसे संकेत हैं, जिन्हें सरकार के लिये गंभीरता से स्वीकार करने की आवश्यकता है।

सरकार, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक लोकप्रियता नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की है। महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, निर्यात बढ़ाना, आयात निर्भरता कम करना और वित्तीय अनुशासन स्थापित करना समय की मांग है। कुछ निर्णय अलोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन अर्थ व्यवस्था को देखते हुए कठोर निर्णय लेने से सरकार बचेगी, तो आने वाले वर्षों में कहीं बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अर्थव्यवस्था केवल प्रचार और आंकड़ों के सहारे नहीं चलती है। अंततः उत्पादन, रोजगार, निवेश, निर्यात और नागरिकों की क्रय शक्ति ही किसी देश की वास्तविक आर्थिक ताकत का निर्धारण करती है। इसलिए समय रहते चेतावनी के इन संकेतों को समझना, समय रहते सुधारात्मक कदम उठाना सरकार और आम जनता के हित में होगा।

टूटे समाजों में भरोसा लौटाने के लिए सम्मान

दुनिया में सैनिकों की पहचान अक्सर युद्ध और सीमाओं से जुड़ी होती है। लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं, जो वर्दी पहनकर केवल सुरक्षा ही नहीं देते, बल्कि भरोसा, संवेदनशीलता और उम्मीद भी बांटते हैं। भारतीय सेना में मेजर अभिलाषा बराक आज ऐसी ही पहचान बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 'यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड' के लिए चुना है।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और किशोरियों के बीच विश्वास निर्माण, संवाद और संवेदनशील नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह उपलब्धि सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की सफलता नहीं है। यह उस भारत की कहानी है, जहां बेटियां अब केवल सपने नहीं देख रहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं।

अभिलाषा बराक का संबंध हरियाणा के रोहतक से है। उनका बचपन सेना के अनुशासन और देशभक्ति के माहौल में बीता। उनके पिता कर्नल एस. ओम सिंह भारतीय सेना में रहे हैं। परिवार की सैन्य परंपरा ने अभिलाषा के व्यक्तित्व को प्रभावित किया। तभी उनके भीतर देशसेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन का लक्ष्य बनती चली गई। हालांकि उनका जन्म तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल में हुआ, लेकिन परिवार की जड़ें रोहतक से जुड़ी रहीं।

अभिलाषा ने जब भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनकर इतिहास रचा, तब हरियाणा ने उन्हें गर्व के साथ 'रोहतक की बेटी' कहा। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया।

साल 2022 भारतीय सेना के इतिहास में एक अहम मोड़ आया, जब अभिलाषा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनीं। यह भारतीय सेना के बदलते स्वरूप का प्रतीक भी थी। लंबे समय तक सेना के लड़ाकू और एविएशन विंग को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा। महिलाओं की भूमिका सीमित समझी जाती थी। उन्होंने यह साबित किया कि साहस, नेतृत्व और क्षमता का कोई लिंग नहीं होता। उनकी इस उपलब्धि ने देशभर की हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि अब भारतीय सेना में महिलाओं के लिए कोई 'सीलिंग' नहीं बची है।

आज संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं। उनका उद्देश्य संघर्ष प्रभावित समाज में भरोसा बहाल करना भी है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के तहत तैनात भारतीय बटालियन में अभिलाषा बराक महिला सहभागिता दल की

कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। युद्ध प्रभावित इलाकों में महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में महिला सैनिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे स्थानीय महिलाओं से ज्यादा सहज संवाद स्थापित कर पाती हैं। अभिलाषा बराक ने लेबनान में महिलाओं और किशोरियों के साथ संपर्क कार्यक्रम चलाए, सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और शांति सैनिकों को लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने यह दिखाया कि एक सैनिक केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास का चेहरा भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने उनके इसी मानवीय नेतृत्व और संवेदनशील कार्यशैली को सम्मानित करने का फैसला किया।

मेजर अभिलाषा बराक इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाली भारत की तीसरी महिला अधिकारी हैं। उनसे पहले सुमन गुवानी और राधिका सेन भी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित हो चुकी हैं। मेजर सुमन गवानी को दक्षिण सूडान में महिलाओं के अधिकारों और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए सम्मान मिला था। वहीं मेजर राधिका सेन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और सामाजिक भरोसा कायम करने की दिशा में अहम कार्य किया। अब अभिलाषा बराक का इस सूची में शामिल होना भारतीय महिला सैन्य नेतृत्व की निरंतर बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

एक समय था जब हरियाणा को बेटियों के प्रति रूढ़ सोच वाले राज्य के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज वही हरियाणा खेल, सेना, विज्ञान और प्रशासन में देश को नई पहचान देने वाली बेटियां दे रहा है। अभिलाषा बराक इसी बदलाव का सबसे मजबूत चेहरा हैं। उनकी उपलब्धि यह भी दिखाती है कि यदि अवसर, शिक्षा और विश्वास मिले तो भारतीय महिलाएं किसी भी क्षेत्र में विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं। अभिलाषा बराक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने सैनिक की कठोर छवि के भीतर मानवीय संवेदना को जीवित रखा। उन्होंने दिखाया कि शांति मिशन केवल सीमाओं की निगरानी नहीं, बल्कि टूटे हुए समाज में भरोसा लौटाने की जिम्मेदारी भी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 'जेंडर एडवोकेट' यानी लैंगिक समानता की पैरोकार के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया।

दिनेश भारद्वाज

आज जब युवा पीढ़ी त्वरित सफलता और सोशल मीडिया की चमक से प्रभावित है, तब मेजर अभिलाषा बराक जैसी शख्सियतें यह याद दिलाती हैं कि असली पहचान मेहनत, अनुशासन और सेवा से बनती है। अभिलाषा की कहानी केवल एक सैन्य अधिकारी की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जहां बेटियां सीमाएं नहीं, संभावनाएं देखती हैं। जहां वर्दी केवल ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का चेहरा भी बन रही है।

गूंज असर : ऊष्मा पेट्रोलियम के सामने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

माही की गूंज, शुजालपुर।
अजय राज केवट

लंबे समय से विवादों और शिकायतों के केंद्र बने राणोगंज स्थित ऊष्मा पेट्रोलियम के सामने किए गए अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मामले को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। वहीं, माही की गूंज द्वारा लगातार प्रमुखता से ''अतिक्रमण मामले में प्रशासन की चुप्पी'' शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

बताया जा रहा है कि, ऊष्मा पेट्रोलियम के सामने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मामले को लेकर कई बार

जनसुनवाई, तहसील कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें भी दी गई थीं।

स्थानीय लोगों का आरोप था कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई से बचता रहा, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते गए। लेकिन जब मामला लगातार मीडिया में उठाया गया तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की और बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाया।

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ती। लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी प्रशासन इसी तरह अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा।

स्थानीय नागरिकों ने कहा कि माही की गूंज ने जनहित के इस मुद्दे को लगातार उठाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद कार्रवाई संभव हो सकी। लोगों ने समाचार पत्र की पहल की सराहना करते हुए अन्य लंबित समस्याओं पर भी ध्यान देने की मांग की।

अतिक्रमण मामले में प्रशासनिक चुप्पी

43 दिन की छुट्टी के बदले मांगी घूस

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर वन विभाग के कार्यालय में दबिश देकर स्थापना शाखा में पदस्थ एक बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। लोकायुक्त की इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे वन विभाग दफ्तर में हड़कंप मच गया और कई अधिकारी-कर्मचारी मौके से खिसकते नजर आए। आरोपी बाबू की पहचान कृष्ण प्रताप सिंह राठौर के रूप में हुई है, जो अपने ही विभाग के एक कर्मचारी को परेशान कर रहा था।

छुट्टी के लिए मांगी घूस

पूरा मामला वन विभाग के ही एक वन रक्षक ललित मीणा की छुट्टियों से जुड़ा हुआ है। ललित मीणा ने अपने 43 दिनों के अर्जित अवकाश को मंजूर कराने के लिए सरकारी आईएफएमआईएस पोर्टल पर आवेदन किया था। इस छुट्टी को आगे बढ़ाने और स्वीकृत कराने के नाम पर स्थापना शाखा के बाबू कृष्ण प्रताप सिंह राठौर ने उनसे 3 से 4 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। वन रक्षक ललित मीणा रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी गुप्त शिकायत सीधे उज्जैन लोकायुक्त दफ्तर में कर दी।

केमिकल लगे नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार

लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया। तय योजना के मुताबिक, जैसे ही वन रक्षक ललित मीणा ने तीन हजार रुपये की रकम बाबू कृष्ण प्रताप सिंह राठौर को थमाई, वैसे ही घात लगाकर बैठी लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया। बाबू के हाथ धुलवाते ही वे गुलाबी हो गए। लोकायुक्त की टीम ने आरोपी बाबू को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कच्चे मकान में लगी भीषण आग

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के मुख्य बाजार माणकचौक में सोमवार- मंगलवार देर रात करीब तीन बजे एक मिट्टी व लकड़ी से बने कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में घर के अंदर रखा पूरा घरेलू सामान व दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के दौरान मकान में फंसे दंपती ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने तीन वर्षीय मासूम बच्चे के साथ खिड़की से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जहां आग लगी वहां आसपास होजयरी और कपड़ों की दुकानें है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

घनश्याम राठौर अपनी पत्नी और तीन वर्षीय बेटे के साथ मकान में रहते हैं। नीचे शादियों में उपयोग होने वाली सामग्री की छोटी दुकान संचालित होती है, जबकि ऊपर परिवार निवास करता है। घटना के समय परिवार सो रहा था। इसी दौरान नीचे के तल में अचानक आग लग गई।

बच्चे को गोद में लेकर खिड़की तक पहुंचे और वहां से नीचे छलांग लगा दी

देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैल गईं और पूरे घर में धुआं भर गया। मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता बंद होने पर दंपती अपने बच्चे को गोद में लेकर खिड़की तक पहुंचे और वहां से नीचे छलांग लगा दी। मकान की ऊंचाई कम होने से तीनों सुरक्षित बच गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आगजनी में घर के अंदर रखे कपड़े, जरूरी दस्तावेज, राशन सहित अन्य कीमती घरेलू सामग्री पूरी तरह जल गई। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण बिजली लाइन में शार्ट सर्किट माना जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि पास के एक मकान का भी हिस्सा भी उसकी चपेट में आ गया।

चिंगारी दिखी, देखते ही देखते आग फैल गई

पीड़ित घनश्याम राठौर ने बताया कि पत्नी को नीचे मीटर से चिंगारी उठती दिखाई दी थी। मैंने वायरिंग काटने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग फैल गई। इस दौरान घनश्याम के दोनों कंधे भी झुलस गए। मेन सर्विस लाइन में शार्ट सर्किट हुआ था। आग फैलने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऊपर खिड़की से कूदकर जान बचानी पड़ी। पहले मैं नीचे कूदा, फिर बच्चे और पत्नी को नीचे लिया। फायर ब्रिगेड में आग बुझाने का पर्याप्त पानी नहीं था। करीब छह फायर लारी आई, लेकिन सभी आधी खाली थी। विद्युत विभाग द्वारा भी समय पर बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई।

बाइक पर बनाया सुसाइड वीडियो, लगा ली फांसी

माही की गूंज, रतलाम।

कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के सेमलिया गांव में एक युवक ने सोमवार शाम गांव के बाहर खेत पर नीम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने बाइक चलाते हुए मोबाइल से वीडियो बनाया, जिसमें उसने पत्नी, साली और साली के पति पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए है। वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान राकेश के स्वजन कालूखेड़ा थाना पहुंचे और वीडियो में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन सौंपा है। इसके बाद गांव के शमशान घाट पर राकेश का अंतिम संस्कार किया गया।

सेमलिया गांव निवासी 33 वर्षीय राकेश चौहान शाम करीब 6रू30 बजे घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर स्वजन उसकी तलाश में निकले। रात करीब 9 बजे उसका शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मंगलवार को एक वीडियो सामने आया। बाइक चलाते हुए राकेश ने कहा कि मेरी शादी हुई थी चिकलाना में रूबी और रीना के वहां पर। आज मैं फांसी खाके मर रहा हूं रीना और उसके पति अंतर सिंह राठौड़ की वजह से। क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के मामले में उसका हाथ है। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करी अंतर सिंह राठौड़ लामगिरी वालों ने। अब मैं फांसी खाके मरूंगा, मेरे कुएं पे, निजी कुएं पे। उसका जिम्मेदार है रूबी और उसका आदमी अंतर सिंह राठौड़ और अब मैं मेरी इच्छा मृत्यु से मरने के लिए तैयार हूं, फांसी खाके मरूंगा क्योंकि मैं इस जिंदगी से परेशान हो गया हूं। मुझे इस औरत ने बहुत परेशान किया है। इसको हजार, दो हजार, पांच हजार, दस हजार, लाखों रुपये की मन्नतें पूरी कर चुका हूं। अभी आठ दिन पहले इसने कहा मुझे दो लाख रुपये चाहिए। मैंने नीलम चौहान के नाम के खाते में पैसे डाले हैं। मेरा अकाउंट चेक करिए। अब मैं मरूंगा और मरने के बाद मेरी संपत्ति का मालिक मेरा लड़का होगा। कालूखेड़ा थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि राकेश और रूबी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों एक-दुसरे से अलग रह रहे है। मृतक के वीडियो की जानकारी इंटरनेट मीडिया से मिली है। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।

पट्टों की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे वार्डवासी

माही की गूंज, मंदसौर।

नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में पट्टे नहीं मिलने से नाराज क्षेत्रवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि कमलेश सोनी लाला के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं रखीं। बड़ी संख्या में पहुंचे रहवासियों ने प्रशासन से लंबित पट्टों का शीघ्र वितरण करने और पात्र लोगों को आवासीय पट्टे प्रदान करने की मांग की। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पार्षद प्रतिनिधि कमलेश सोनी लाला ने बताया कि वार्ड क्रमांक 2 में बड़ी संख्या में गरीब एवं मजदूर वर्ग के परिवार निवास करते हैं। प्रशासन द्वारा समय-समय पर पात्र लोगों को रहने के लिए पट्टे दिए जाते हैं, लेकिन लंबे समय से वार्ड में पट्टों का वितरण नहीं हुआ है। कुछ समय पहले जारी हुई सूची में शामिल कई लोगों को भी अब तक पट्टे प्राप्त नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पट्टा नहीं होने के कारण कई परिवारों को बिजली, पानी और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर वार्डवासियों में आक्रोश है और जनप्रतिनिधियों को लगातार लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

मामले की जानकारी मिलने पर विधायक विपिन जैन भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर वार्डवासियों की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। विधायक ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर पट्टे मिलना चाहिए ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक और नगर पालिका अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुनवाई की। पार्षद प्रतिनिधि कमलेश के अनुसार प्रशासन ने मौके पर ही 10 पट्टे जारी कर दिए। उन्होंने कहा शेष पात्र लोगों को भी जल्द पट्टे उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

जिलाध्यक्ष के काफिले पर गोफन से हमला

माही की गूंज, रतलाम।

मंगलवार रात करीब आठ बजे रावटी के समीप ग्राम आमलीपाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय के काफिले पर गोफन से अज्ञात लोगों ने पत्थर मारे। इस घटना में कार के कांच फूट गए जबकि अंदर उपाध्याय के साथ बैठे युवक चिराग को सिर पर चोट पहुंची। कार में भाजपा उपाध्यक्ष जुबिन जैन भी थे। उपाध्याय ने बताया कि वे उपाध्यक्ष जुबिन जैन की कार में सवार होकर रावटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रावटी से पहले अमलीपाड़ा में गोफन से पथराव हुआ, लेकिन वाहन रूकने नहीं दिया। रावटी पहुंचकर कार रोकी। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र में देर रात तक असामाजिक तत्वों के घूमने से भी वारदातें हो रही है। क्षेत्र में लगातार वारदातें हो रही हैं। पुलिस की लापरवाही और ढिलाई से बदमाशों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते वे लगातार बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही वारदातों से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है और वे मामले में पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की लगातार मांग कर रहे हैं।

मंगलवार रात फिर ऐसी वारदात सामने आ गई। इसमें भाजपा नेता के वाहन पर पथराव किया गया। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना किसी गंभीर घटनाक्रम होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। जिम्मेदार भी इस ओर से आंखें मूंदें बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार तभी जागेंगे जब कोई बड़ा घटनाक्रम या वारदात यहा हो जाएगा। क्षेत्र में असामाजिक तत्वों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। वे बेखौफ होकर लगातार वारदात कर रहे हैं। मंगलवार रात को हुए हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो जिम्मेदार क्या जवाब देते, यह उनको सोचना चाहिए। यहां के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर व्यवस्था करना चाहिए।

शासकीय महाविद्यालय में स्वीकृत हुआ एमबीए और एमसीए कोर्स

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में स्थित शासकीय महाविद्यालय में अब विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स एमबीए और एमसीए भी कर सकेंगे। इसके लिए स्वीकृति 1 जून 2026 सोमवार को उज्जैन से मंदसौर महाविद्यालय को प्राप्त हुई है। शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने बताया कि लम्बी कागजी लड़ाई के बाद मंदसौर को यह उपलब्धि मिली है। अब मंदसौर के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं भी एमबीए, एमसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स बेहद नाम मात्र की फीस में करके अपना भविष्य बना सकेंगे। चंदवानी ने बताया कि पूर्व में जनभागीदारी के प्रयासों से बीबीए और बीसीए जैसे कोर्स महाविद्यालय में संचालित हो रहे थे अब मास्टर डिग्री के रूप में एमबीए और एमसीए की स्वीकृति भी मिल गई इससे जिले भर के विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। अभी दोनों कोर्स के लिए 30 - 30 सीटें आवंटित हुई है।

महिलाओं को दिन दहाड़े लूटने वाले गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

पुलिस ने दिनदहाड़े बाजना बस स्टैंड और रावटी में महिलाओं से सोने की नथ लूटने वाले दो शातिर आरोपितों को घटना के महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में रावटी के ग्राम नरसिंग नाका निवासी 19 वर्षीय विष्णु पुत्र बागजी मईड़ा व मलवासी नाका निवासी 19 वर्षीय मोहन पुत्र शैतान भाभर शामिल है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

एसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि, माणकचौक थाना पुलिस व साइबर सेल ने एएसपी विवेक कुमार के मार्गदर्शन में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को फरियादी जगदीश मईड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 12रू30 बजे बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उसकी पत्नी वज्जा बाई को डराकर नाक में पहनी सोने की नथ छीन ली थी। थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की सहायता से संदिग्धों की पहचान की।

दोनों को ट्रेस करते हुए पुलिस देर रात रावटी पहुंची जहां से संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपितों ने बाजना बस स्टैंड क्षेत्र के 30 मई को रावटी से मजदूरी कर अपने घर ग्राम बीड़ लौट रही 59 वर्षीय सेनाबाई पत्नी पूना भाभर के साथ शाम करीब 6 बजे लूट की थी।

सेना बाई से लूटी गई 9 ग्राम वजनी सोने की नथ को आरोपितों ने 30 हजार रुपये में गिरवी भी रख दिया था, जिसे पुलिस ने मेमोरेण्डम के आधार पर बरामद किया। आरोपितों से 5 ग्राम वजनी सोने की नथ कीमत करीब 80 हजार रुपये, बाइक (क्रमांक एमपी43 जेडएन 7458) 26150 रुपये नकद व दो मोबाइल जब्त किए। 9 ग्राम वजनी सोने की नथ की कीमत करीब 1 लाख 30 हजार रुपये है।

शराब लेने पहुंचे और पकड़ में आ गए

शिवगढ़ के ग्राम डूंगरा पुंजा निवासी वज्जाबाई अपने पत्नी जगदीश मईड़ा व दो वर्षीय बेटे के साथ बड़नगर मजदूरी पर गए थे। बड़नगर से गांव लौटने के लिए बाजना बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक पर आए दोनों बदमाशों ने उन्हें डराया और उसकी पत्नी की नाक से नथ छीनकर फरार हो गए।जगदीश ने शोर मचाकर पीछा भी किया। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी चेक किए और आरोपितों की लोकेशन ट्रेस कर ली।आखरी बार आरोपित रावटी की शराब दुकान पर कैद हुए।

बस पुलिस ने वहीं आसपास इनकी तलाश की और दोनों पकड़े गए। आरोपितों से पूछताछ के दौरान मोबाइल में रावटी की लूट के भी साक्ष्य मिल गए। घटना में जिन घरों व दुकानों के सीसीटीवी कैमरों से सहायता मिली है। उन्हें लगवाने वालो को एसपी अमित कुमार द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

पुष्पा झुकेगा नहीं, लिखी पिकअप में मिली सागौन लकड़ी तस्कर फरार

माही की गूंज, खंडवा।

कालीभीत के जंगल में वन विभाग ने सागौन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन जब्त किया है। वाहन में करीब पौने दो लाख रुपए मूल्य की तीन घनमीटर सागौन लकड़ी भरी हुई थी। कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जबकि वाहन और लकड़ी वन विभाग के कब्जे में ले ली गई।

यह कार्रवाई पश्चिम कालीभीत वन परिक्षेत्र के सिरालिया उप परिक्षेत्र अंतर्गत भुरकुला जंगल क्षेत्र में मंगलवार देर रात की गई। नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को जंगल के भीतर एक वाहन की रोशनी दिखाई दी। रात के समय जंगल में वाहन की मौजूदगी संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और तत्काल घेराबंदी की गई।

वन विभाग की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वाहन में सवार लोग विभागीय वाहनों की रोशनी देखकर पिकअप छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। जब वनकर्मी वाहन तक पहुंचे तो उसमें कोई मौजूद नहीं था। वाहन बंद होने के कारण उसका ताला तोड़कर तलाशी ली गई, जिसमें सागौन के 20 लट्ठे बरामद हुए। इसके बाद वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया गया।

कार्रवाई के बाद जब्त पिकअप वाहन उस पर लिखे संदेशों के कारण भी चर्चा में रहा। वाहन के एक तरफ बड़े अक्षरों में पुष्पा झुकेगा नहीं साला तथा दूसरी ओर पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, हम फायर हैं लिखा हुआ था। वन विभाग की कार्रवाई के बाद ये फिल्मी संवाद भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।

वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रम सिंह भदौरिया ने बताया कि यह वाहन पहले भी कई बार देर रात जंगल क्षेत्र में देखा गया था। विभाग को इसकी गतिविधियों पर पहले से संदेह था, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इस बार वाहन से सागौन लकड़ी बरामद होने के बाद संदेह की पुष्टि हो गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब्त पिकअप वाहन वनग्राम कोटवारिया निवासी रामकिशन पाटिल के नाम से संबंधित बताया जा रहा है। वन विभाग वाहन स्वामी सहित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रहा है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जिले को मिली 13.74 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात

माही की गूंज, खंडवा।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चार महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं पर कुल 13 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत आएगी तथा 14.44 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे जिले के कई गांवों की लंबे समय से चली आ रही सड़क संबंधी मांग पूरी हो सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़क निर्माण से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों और मरीजों को आवागमन की बेहतर व्यवस्था मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वीकृत परियोजनाओं में बरमलाय से कुकडाल मार्ग का 7.64 किलोमीटर लंबा निर्माण कार्य शामिल है, जिस पर 7 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बरमलाय से सुकलतालाई-4 मार्ग के 3.20 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं लहाड़पुर से पारवाड़ी मार्ग के 2.24 किलोमीटर हिस्से पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए तथा मालूद मार्ग से खेड़ी रैयत मार्ग के 1.36 किलोमीटर हिस्से के निर्माण पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मुख्य मार्गों से बेहतर होगा। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में आवागमन की समस्या से जूझने वाले गांवों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में विकास गतिविधियों को गति मिलेगी और ग्रामीण जनजीवन अधिक सुगम बनेगा।

मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारी

माही की गूंज, बड़वानी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन जिले में तेज हो गया है। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत कर्मचारी पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने नियमितीकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता तथा वेतन विसंगतियों के निराकरण सहित आठ सूत्रीय मांगें रखी हैं। उनका आरोप है कि शासन स्तर पर कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक मांगों का समाधान नहीं हो सका है।

कर्मचारियों ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया था तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे गए थे। इसके बाद अब कर्मचारी विभागीय कार्यों का बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

संघ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की अनेक योजनाओं और सेवाओं के संचालन में एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं और लाभ नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

संघ के पदाधिकारियों के अनुसार आगामी 8 जून को प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय रहते उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है।

छात्रावास की समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं छात्राएं

माही की गूंज, बड़वानी।

शासकीय कन्या अनुसूचित जाति महाविद्यालय छात्रावास क्रमांक-1 एवं 2 की 50 से अधिक छात्राएं बुधवार को अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने छात्रावास की वार्डन पर राशन में कटौती, दुर्व्यवहार तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।

छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। उनका आरोप है कि नलकूप सीमित समय के लिए संचालित होता है और कई बार बंद भी रहता है, जिससे 100 से अधिक छात्राओं को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। छात्रा जागृति सोलंकी ने बताया कि गर्मी के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। पानी संग्रहण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया।

छात्राओं ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से उन्हें नए गद्दे और चादरें नहीं मिली हैं। छात्रावास में उपलब्ध संगणक भी उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इंटरनेट सुविधा बंद है। इसके अलावा नए पंखे लगाने का आश्वासन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई छात्राओं को पिछले छह से सात माह से छात्रवृत्ति और अन्य देय राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत भी है।

राशन वितरण को लेकर भी छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले मिलने वाली खाद्यान्न सामग्री की मात्रा में कमी कर दी गई है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि इस संबंध में पूछने पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। छात्राओं ने वार्डन पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की।

छात्राओं ने यह भी बताया कि छात्रावास की पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक पुस्तकों का अभाव है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

वहीं, वार्डन वंदना चौहान ने छात्राओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि बजट की कमी के कारण कुछ व्यवस्थाओं में परेशानी आ रही है, लेकिन छात्रावास में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने राशन में कटौती और दुर्व्यवहार के आरोपों को भी खारिज किया।

छात्राओं का कहना है कि वे पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित समाधान की मांग की है।

चीन की दूरदृष्टि से सबक लेने की जरूरत

ब्लूमबर्ग न्यूज की 28 जनवरी, 2026 की खबर के अनुसार, चीन ने पिछले साल सभी तकनीकी क्षेत्रों में 543 गीगावाट जितनी नई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत में 2024 के आखिर तक के पैदा हुए कुल बिजली उत्पादन से 12 प्रतिशत ज्यादा है। चीन की इस बढ़ोतरी में 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का था, जिसमें सोलर व पवन ऊर्जा शामिल हैं। वहीं यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है (लगभग 1.4 अरब बैरल)। दिलचस्प कि उसने 2025 में अपने तेल भंडारण में काफी वृद्धि की, और रूस, ईरान और वेनेजुएला से रियायती दरों पर करोड़ों बैरल तेल खरीदा। जबकि भारत के पास सिर्फ 21 मिलियन बैरल का तेल भंडार था।

पिछले कुछ दशकों में, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन, लिथियम-आयन बैट्री उत्पादन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी जबरदस्त रणनीतिक बढ़त बनाई है। चीनी लोग इस समूची मूल्य संवर्धन शृंखला में अब दुनियाभर में अग्रणी हैं। ऐसा कर उन्होंने न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की और प्रदूषण घटाया बल्कि जीवाश्म ईंधन से दूर हटती दुनिया के दौर में अपनी बहुत मजबूत स्थिति भी बना ली। रेयर अर्थ मिनरल, ईवी निर्माण, बैट्री उत्पादन व स्वच्छ ऊर्जा की यह तिकड़ी, किसी अर्थव्यवस्था की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने का 'सबसे अहम माध्यम' है।

यह सब सावधानी से की गई योजनाबंदी से हासिल हो पाया, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया (अभी वहां 15वीं योजना चल रही है)। ये योजनाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद (चीनी कैबिनेट) मिलकर बनाती हैं। यह रणनीतिक बढ़त ही तय करेगी कि देश आगामी ऊर्जा संकट से कैसे निबटेगा। यह ऊंची और नीची महंगाई दर वाले देशों के बीच का फर्क बनाता है, और यह तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा कि एआई के युग में डेटा सेंटर कहां स्थापित होंगे, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, रेयर अर्थ मिनरल और डेटा सेंटरों के बीच एक रणनीतिक सांझ है। बीते साल चीन ने अपने रणनीतिक अस्त्र का इस्तेमाल किया व रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाकर भारत का ईवी उत्पादन करीब ठप कर दिया था (इस क्षेत्र में उसका लगभग एकाधिकार है)।

देश -अपनी सरकारों के जरिए- भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। ऐसी योजना में विगत के और मौजूदा अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करना शामिल होता है, साथ ही भविष्य के संभावित बदलावों के बारे में भी अनुमान भी लगाए जाते हैं। उपरोक्त अवयवों के आधार पर, सरकार भविष्य से निबटने को नीतियां बनाती है। जब हम खुद को और अपनी मौजूदा स्थिति को, खासकर ऊर्जा की स्थिति और उसके नतीजों के मामले में, देखते हैं, तो लगता है कि हमने पिछले कुछ दशक में जरूरी तैयारी नहीं की।

चूंकि भारत का अपना तेल का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए यह यकीनी बनाना केंद्र की जिम्मेदारी है कि आपात स्थिति में संसाधन उपलब्ध रहें, पर्याप्त भंडार बनाए, और इससे भी ज्यादा जरूरी यह कि बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा अपनाएं, ताकि हम आयातित कच्चे तेल पर बिल्कुल निर्भर न रहें। जहां यह बात तसल्ली देने वाली है कि हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीकरणीय स्रोतों से आता है, लेकिन कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा अभी भी सबसे अधिक (लगभग 42 प्रतिशत) है। अहम बात यह है कि यह अभी भी कुल बिजली खपत का 70 प्रतिशत हिस्सा मुहैया करवाता है, जबकि भारत ने अभी तक बिजली के भंडारण की पर्याप्त क्षमता विकसित नहीं की। जबकि चीन ने इस मामले में बहुत काम किया है। यह दशक लगातार उथल-पुथल भरा रहा। पहले कोविड महामारी, फिर पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया युद्ध जो जारी हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उद्भव। भारत औद्योगिक क्रांति करने से चूक गया था, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश '80 और '90 के दशक के कंप्यूटर-प्रधान युग के शुरुआती दौर में भी चूक कर गयाय '90 के दशक के आर्थिक सुधार तब जाकर लागू किए, जब देश करीब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। शुक्र है, निजी क्षेत्र ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली, साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की बड़ी फौज ने भी स्थिति से उबारने में मदद की। हालांकि भारत अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, आईटी क्षेत्र में उसकी जगह अधिकांशतः सेवा आधारित क्षेत्र में ही है।

हालांकि देर से हुई शुरुआत के मद्देनजर, काबिल-ए-तारीफ है कि हम इतनी प्रगति कर पाए। एआई से आ रहे बड़े बदलावों की बात करें तो, हमने एक बार फिर मौका गंवा डाला है और अब हम उसे तेजी से दूर जाते हुए देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में हमारी कोई जगह नहीं, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपूर्ति के लिए एशियाई दिग्गजों- ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन पर निर्भर बना हुआ है। जिन डेटा सेंटर्स की स्थापना की योजना बनाई जा रही, वे भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे। अमेरिका और चीन ने एआई और उससे जुड़े बुनियादी ढांचा निर्माण में बहुत बड़ी छलांग लगाई। इस आधारभूत ढांचे में बेहतरीन चिप बनाना, सस्ती बिजली और सरकार का योगदान बतौर सुधारक और मददगार होना शामिल है। एनवीडिया सरीखी कंपनियां अब खरबों डॉलर मूल्य की बन चुकी हैं और एआई तकनीक का प्रवाह नियंत्रित करती हैं। किसे ये चिप्स मिल सकती हैं और किसे नहीं, अमेरिका ही तय करता है। एएसएमएल जैसी डच कंपनियां -जो बेहतरीन क्वालिटी के माइक्रोचिप्स उत्पादन के लिए मशीनें बनाती हैं और इस क्षेत्र में उनका करीब एकाधिकार है- सिर्फ उनको ही बेच सकती हैं, जिसकी इजाजत अमेरिका देता है।

इन सब के बीच हम कहां खड़े हैं? क्या हम एक बार फिर से केवल सेवा और रखरखाव प्रदाता बनने की उम्मीद पाले हैं? जिस स्तर का ऑटोमेशन व रोबोटिक्स सामने आ रहा है, उसे देखकर लगता है, हमारी यह भूमिका भी बहुत छोटी होकर रह जाएगी।

एआई के इस दौर में, अपनी बादशाहत कायम करने की होड़ में जब अलग-अलग देशों के रणनीतिक हित आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसे में एक समझदार और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है। एआई आधारभूत तंत्र विकास और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक साझेदारियां बनाने में विदेश नीति और कूटनीति की अहम भूमिका होगी। आज की तारीख में, यहां तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रिड स्टोरेज के हेतु बैट्री बनाने की हमारी क्षमता चीन से आयातित 'दुर्लभ खनिजों' पर निर्भर है (इस क्षेत्र में भी चीन का लगभग एकाधिकार)। रणनीतिक गठबंधनों की जरूरत हमें गैस की कमी, और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बंद हो जाने से पैदा हुई उर्वरकों और कच्चे तेल की संभावित कमी व आपूर्ति शृंखला में रुकावटों के रूप में साफ दिखती है। हमें मजबूरन हाथ-पैर मारने पड़ रहे, दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। रूस संग हमारा भी समझौता था, चीन की तरह, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों का सर्वाधिक नुकसान हमें उठाना पड़ा।

इसी तरह, अब हमें ईरान से भी तेल नहीं मिल पा रहा है। हमारी भंडारण क्षमता भी सीमित है, और हमने हाल ही में यूएई के साथ मिलकर बड़े-बड़े तेल भंडार बनाने का समझौता किया है... लेकिन इसको फलीभूत होने में अभी काफी समय लगेगा। अमेरिका-ईरान युद्धबंदी वार्ता नाकाम होना हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा और इससे अफरा-तफरी मच सकती है - ऐसी स्थिति से हम अब तक किसी तरह बचे हुए थे। इसके साथ ही, अमेरिका पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल की पीठ ठोक रहा है, और ईरान के मामले में उस पर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में भरोसा करता है। आर्थिक दुश्वारियों से राहत पाने में अमेरिका ने विश्व बैंक के जरिए उसकी मदद की है।

गुरबचन जगत

भारत की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली बात है चीन और पाकिस्तान के बीच के करीबी रिश्ते। चीन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया, और दोनों के बीच की 'पहाड़ों से भी ऊंची' दोस्ती का वचन एक बार फिर दोहराया। जारी संयुक्त बयान में, लंबे समय से चले आ रहे 'जम्मू और कश्मीर विवाद' को सुलझाने की बात कही गई। चीन हमारे पूर्वोत्तर में निरंतर बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है, खासकर उन इलाकों में जिन पर वह अपना दावा जताता आया है। मणिपुर में पिछले तीन सालों से चली आ रही समस्या और नगालैंड एवं मिजोरम के पुराने नासूर बताते हैं कि पूर्वोत्तर में हमारी अपनी स्थिति भी खास अच्छी नहीं है। बांग्लादेश में हाल ही में चुनी गई नई सरकार पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वह पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है, और पूर्वोत्तर में हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने में सक्षम है। इन अवयवों को एक साथ देखें -ऊर्जा की स्थिति, जिसके और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका हैय चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हमारे प्रति रवैयाय और हमारी अपनी अंदरूनी समस्याएं- तो इस समय बेहद सूझवान राजनेता और उच्च कोटि की कूटनीति की जरूरत है।

इस चौतरफा हमले का सामना करने के लिए पूरे देश का एकजुट रहना जरूरी है। इस पहल की शुरुआत भारत सरकार के नेतृत्व से होनी चाहिए।

लंबित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने अधिकारों, लंबित मानदेय के भुगतान और सामाजिक सुरक्षा की मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ) के बैनर तले आज, 3 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से दाहोद नाका (समाधि स्थल), आलीराजपुर में एक दिवसीय विशाल आंदोलन और रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की जाएगी।

संघ के पदाधिकारियों ने जिले की सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस आंदोलन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आह्वान किया है।

दिसंबर 2024 से अटका है मानदेय, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश

संघ की जिला अध्यक्ष कमला रावत ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कई गंभीर समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं।

800 कार्यकर्ताओं का भुगतान बकाया

जिले की लगभग 800 मिनी से पूर्ण आंगनवाड़ी में पदोन्नत कार्यकर्ताओं का दिसंबर 2024 का शेष मानदेय (5250) आज तक नहीं मिला है।

नई नियुक्तियों को 9 महीने से नहीं मिला पैसा

नई भर्ती में नियुक्त कई सहायिकाओं को पिछले 8 से 9 महीनों से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं का पूर्व का रोका गया मानदेय भी अटका हुआ है। संघ ने चेतावनी दी है कि समस्त लंबित राशि का एकमुश्त भुगतान तत्काल किया जाए।

महत्वपूर्ण काम के बदले मिलता है केवल आश्वासन

संघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंजुला लोहार ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण अभियान, टीकाकरण, चुनावी सर्वे और जनगणना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अग्रिम पंक्ति की होती है। इसके बावजूद शासन स्तर पर उन्हें उनका वाजिब हक और सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है।

वही इस बारे में धनसिंग कनेश, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जुटकर अपनी एकजुटता का परिचय दें।

आंगनवाड़ी संघ ने अपनी मांगों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है

1. शासन स्तर की प्रमुख मांगें-

- शासकीय कर्मचारी का दर्जा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
- पेंशन और ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले।
- भत्ते और पारिश्रमिक: ऑनलाइन और पोषण ट्रैकर कार्य के लिए मोबाइल व इंटरनेट भत्ता दिया जाए, साथ ही चुनाव या सर्वे जैसे अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग से पारिश्रमिक मिले।
- मूलभूत सुविधाएं: सभी केंद्रों पर स्वयं के भवन, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो।

2. जिला स्तर की मांगें:

- दिसंबर 2024 के बकाया ?5250 का तत्काल भुगतान।
- नई सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के रोके गए मानदेय का एकमुश्त भुगतान।
- हर महीने तय समय पर मानदेय जारी करने की व्यवस्था।
- रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपेंगी ज्ञापन

तय रणनीति के अनुसार, बुधवार सुबह 11 बजे दाहोद नाका समाधि स्थल पर जिलेभर की कार्यकर्ताएं एकत्रित हुईं। यहाँ से एक विशाल रैली निकाली गई जो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंगी, जहाँ मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महमूद खान प्रशासनिक अधिकारि को ज्ञापन सौंपा गया। ?इस आंदोलन को सफल बनाने में भारतीय मजदूर संघ जिलामंत्री धनसिंह कनेश,जिला अध्यक्ष कमला रावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंजुला लोहार, सचिव रंजीता कनेश, जिला उपाध्यक्ष कमलबाई मेडा, सरोज चौहान, संगीता डुडवे और प्रीति चौहान सहित संघ के सभी पदाधिकारी सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।

सफाई व्यवस्था को लेकर नागरिकों में नाराजगी

माही की गूंज, च.शे. आजाद नगर।

नगर के प्रमुख आजाद ग्राउंड की सफाई व्यवस्था को लेकर नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मैदान की सफाई केवल 26 जनवरी, 27 फरवरी और 15 अगस्त जैसे विशेष अवसरों पर ही की जाती है, जबकि वर्ष के अन्य दिनों में यहां कचरे के ढेर लगे रहते हैं।

बताया जाता है कि आजाद ग्राउंड के अंदर स्थित के आसपास भी गंदगी का माहौल बना हुआ है। नियमित साफ-सफाई के अभाव में मैदान की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिससे यहां आने वाले नागरिकों और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस संबंध में जब सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे दरोगा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि ,में कहा कहा ध्यान दूं।' वहीं नगर पंचायत के सीएमओ ने बताया कि ÷मेरे पास दो स्थानों का प्रभार है, इसलिए हर जगह नियमित निगरानी करना कठिन हो जाता है। हालांकि सफाई व्यवस्था में जल्द सुधार किया जाएगा।'

नगरवासियों का कहना है कि राष्ट्रीय पर्वों और विशेष आयोजनों के समय ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष आजाद ग्राउंड की नियमित सफाई होनी चाहिए। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से मैदान और गांधी भवन परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, उधर गोदाम से गायब हो गईं 700 बोरियां...

बैतूल।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खाद चोरी का बड़ा मामला सामने आया है. यहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जामठी के वेयर हाउस से करीब 700 बोरी खाद चोरी हो गई। खास बात यह है कि यह चोरी ऐसे समय में हुई है, जब जिले के कई इलाकों में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। समिति के वेयर हाउस से 668 बोरी यूरिया, 32 बोरी पोटाश और 5 बोरी जिंक गायब मिली। चोरी गए खाद की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात अज्ञात चोर ट्रक लेकर वेयर हाउस पहुंचे। उन्होंने गोदाम के ताले तोड़े और खाद की बोरियां ट्रक में भरकर फरार हो गए। सोमवार को जब किसानों को खाद वितरण के लिए गोदाम खोला गया, तब चोरी का खुलासा हुआ। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

इस चोरी ने सिर्फ पुलिस ही नहीं, स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है। जिस वेयर हाउस से चोरी हुई, वहां न तो सुरक्षा गार्ड था, न पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे। यानी जिस गोदाम में किसानों के लिए सैकड़ों बोरी खाद रखी गई थी, उसकी सुरक्षा लगभग भगवान भरोसे थी।

हाइवे के पास गोदाम, फिर भी नहीं लगी भनक

हैरानी की बात यह भी है कि गोदाम हाइवे से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में ट्रक का आना, घंटों तक खाद लोड होना और फिर वहां से निकल जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। कोतवाली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया के मुताबिक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जामठी के वेयर हाउस के ताले टूटे मिले हैं और वहां से करीब 700 बोरी खाद चोरी हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

पहले से खाद संकट झेल रहे किसानों के लिए यह घटना चिंता बढ़ाने वाली है। जिस समय खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो रही हैं, उसी समय खाद का बड़ा स्टॉक गायब हो जाना प्रशासन और सहकारी समिति दोनों के लिए चुनौती बन गया है।

ब्लास्ट के बाद फूटी नर्मदा पाइपलाइन

इंदौर।

मध्य प्रदेश के इंदौर-महू मार्ग स्थित भेरू घाट क्षेत्र में नर्मदा जल प्रदाय परियोजना की एक बड़ी पाइपलाइन फट जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइपलाइन फटने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पाइपलाइन अचानक जोरदार धमाके के साथ फटी और पानी का फव्वारा करीब 150 फीट तक ऊपर उछलने लगा। देखते ही देखते पूरा इलाका पानी से भर गया और भेरू घाट में जलप्रलय जैसे हालात बन गए।

घटना के बाद तेज गति से बहता पानी आसपास के रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच गया। कई घरों के बाहर और गलियों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह का नजारा नहीं देखा था। पाइपलाइन से निकल रहा पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि आसपास मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे।

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन फटने के बाद लंबे समय तक पानी लगातार बहता रहा, लेकिन संबंधित विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी मौके पर समय पर नहीं पहुंचे। लोगों का कहना है कि यदि तत्काल कार्रवाई की जाती तो बड़ी मात्रा में पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए।

पाइपलाइन की मरम्मत में जुटा विभाग

जानकारी के अनुसार यह पाइपलाइन इंदौर शहर को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण लाइन का हिस्सा है। ऐसे में पाइपलाइन फटने से न केवल पानी की भारी बर्बादी हुई है, बल्कि शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है। अधिकारियों को अब पाइपलाइन की मरम्मत और जलापूर्ति व्यवस्था को सामान्य करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

फिलहाल संबंधित विभाग की टीम पाइपलाइन की क्षति का आकलन करने और मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन को दुरुस्त कर जलापूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद इंदौर के कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है और लोगों को जल संकट की आशंका सता रही है।

मयंक सोनी विधायक प्रतिनिधि नियुक्त

माही की गूंज, च.शे. आजाद नगर।

जोबट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 192 की विधायक सेना महेश पटेल द्वारा क्षेत्र के विकास और शासकीय संस्थाओं के सुदृढ़ संचालन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, विधायक सेना महेश पटेल ने चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी सक्रिय युवा नेता मयंक सोनी को शासकीय आई.टी.आई. सेजावाड़ा भाबरा की संस्था प्रबन्धन समिति के गठन हेतु विधायक प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया है।

इस संबंध में विधायक कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेजावाड़ा, चंद्रशेखर आजाद नगर को सूचित किया गया है कि संस्था में समय-समय पर होने वाली आगामी महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना उन्हें विधायक प्रतिनिधि के रूप में प्रदान की जाए।

अनुभवी नेतृत्व को मिली बड़ी जिम्मेदारी

गौरतलब है कि सक्रिय युवा नेता मयंक सोनी इससे पहले भी नगर पंचायत विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं। उनके इस पूर्व अनुभव, जनहित के कार्यों में सक्रियता और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए ही विधायक सेना महेश पटेल ने उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए इस महत्वपूर्ण तकनीकी शिक्षण संस्थान की समिति में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मयंक सोनी की इस नियुक्ति से क्षेत्र के युवाओं और छात्रों में हर्ष का माहौल है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने जताई खुशी

मयंक सोनी की इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के अवसर पर आजाद नगर भाबरा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस उपलब्धि पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मदन डावर, लहीक मो शेख, हरीश भाबर, राजेश जैन, कपिल सोनी, अश्विन भाई बाबू भाई, हनीफ शेख, आदिल शेख, फिरोज खान, अख्लाक नवाबी, शाबीर शेख व समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक होंगे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों की सफल तैयारी एवं क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून को आयोजित होने वाले 'एक पेड़ मां के नाम अभियान-3.0' के तहत स्वदेशी पौधों को प्राथमिकता से रोपित करने, अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा अमृत मित्रों को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि लगाए गए पौधों का संरक्षण एवं समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वच्छता एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जल स्रोतों के गहरीकरण, उनके आसपास साफ-सफाई, प्लास्टिक उपयोग को हतोत्साहित करने तथा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि जिले में 12 से 18 जून तक विशेष जनकल्याणकारी शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों एवं छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

बैठक में आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि 14 जून को देशव्यापी ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रतिभागी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के प्रयास का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल करना होगा, जिसके बाद उनके व्हाट्सएप पर कार्यक्रम से जुड़ने का लिंक प्राप्त होगा। यह योग सत्र प्रातः 6रू15 बजे से 7रू35 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़कर उन्हें इसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि नागरिक स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने के लिए स्वत प्रेरित हों। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 एवं 20 जून को प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम, एडीएम सोहन कनास, संयुक्त कलेक्टर मनोज गरवाल, डिप्टी कलेक्टर तपीस पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

आवेदक द्वारा गलत जानकारी पर होगी कार्रवाई, मगर अफसरों के फर्जी निराकरण पर भी क्या लगेगी लगेगी...?

कलेक्टर के आदेश सही, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए...

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

एक कहावत भी है और मानव प्रवृत्ति भी है कि, हर कोई अच्छा-अच्छा ग्रहण करना चाहता है और बुरे-बुरे को छोड़ देना चाहता है। यानि सीधे तौर पर 'मीठा-मीठा गट और कड़वा-कड़वा थू।' लेकिन हर बार मानव से यह भूल होती है, क्योकि हर सिक्के के दो पहलू होते है। कोई भी सिक्का दोनों तरफ से एक सा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर वह सिक्का, सिक्का ना होकर केवल लोहे का टूकड़ा भर होता है। यह बात एक मिसाल के तौर पर कही गई है, लेकिन जिला प्रशासन की प्रवृत्ति इस पर सटीक साबित होती दिखाई दे रही है।

वर्तमान स्थिति में जिला प्रशासन भी मीठा-मीठा गट और कड़वा-कड़वा थू करने वाली स्थिति में ही दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन व जिम्मेदारों को वाहवाही तो अच्छी लगती है लेकिन उन्हे आलोचनाओं से बड़ा परहेज होता है। खुले तौर यह देखा गया है कि, प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अपनी तस्वीरें और सकारात्मक खबरों को प्रचारित-प्रसारित तो करवाना चाहते है, लेकिन उनकी बुराई और भ्रष्टाचार उजागर हो जाए या छप जाए या प्रचारित-प्रसारित हो जाए तो ये जिम्मेदार बुरा मान जाते है। हालांकि जिला प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों की सोच और मकसद गलत नहीं होता लेकिन वे यह क्यों भूल जाते है कि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है।

पिछले कुछ दिनों में जनसुनवाई में आए कुछ मुद्दे प्रशासन ने ऐसे उजागर किए कि आवेदक ही कटघरे में खड़ा हो गया। आवेदकों द्वारा जनसुनवाई के आवेदन में दी गई जानकारी असत्य और भ्रामक साबित हुई। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि ''जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य आमजन की वास्तविक समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर असत्य, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत प्रस्तुत कर शासन की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा जारी किए गए हैं। कलेक्टर के इस आदेश के साथ जनसुनवाई में आए तो शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्हे आवेदक द्वारा भ्रामक जानकारी देने व तथ्यों को छुपाकर जानकारी प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई।

सही भी है, जनसुनवाई जैसे सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर कलेक्टर के आदेश भी बिल्कुल सही है कि तथ्यों को छुपाकर दी गई भ्रामक जानकारी मिलने पर आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है जो यह दर्शाता है कि, नियम तो सभी पर बराबर लागू होना चाहिए। जब तथ्यों को छुपाकर भ्रामक जानकारी देने वाले आवेदक पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते है तो फिर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए जाना चाहिए जो सही और हकदार आवेदकों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते है या फिर शिकायत को फुटबाल बनाकर आवेदक को एक-दूसरे तक पास करते है। यह विडम्बना ही कही जाएगी कि सरकारें अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है और तंत्र में बैठे अधिकारी उंट पर बैठकर बकरी चराते नजर आते है।

जिले में चल रही जनसुनवाई हो या फिर सीएम हेल्प लाइन की शिकायतें अक्सर यह देखने में आ ही जाता है कि अधिकारी, शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते ही रहते है। या फिर निराकरण के नाम पर कागजी घोड़े दौड़ाकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह जिले के तंत्र में बैठे अधिकारियों की प्रवृत्ति ही बन चुकी है कि शिकायत आई तो माथा उतारनी करके रफा-दफा कर दिया जाए। मगर बहुत से अधिकारी शिकायतकर्ता और आवेदक की मदद करने के बजाय शिकायतकर्ता और आवेदक से ही सेटिंग बाजी में लग जाते है। जब बात लेन-देन और सेटिंग पर खत्म नहीं होती तो फिर दबाव, प्रभाव का इस्तेमाल करने से भी तंत्र में बैठे अधिकारी नहीं चूकते। कुल मिलाकर शिकायतकर्ता को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि येन-केन प्रकारेण वह अपनी शिकायत या तो वापस ले लेता है या फिर जिला प्रशासन से आस छोड़ संभाग या राजधानी की ओर बढ़ जाता है।

चूंकि प्रदेश सरकार द्वारा शिकायत और आवेदन के त्वरित निराकरण के सख्त निर्देश है तो अधिकारी भी किसी का भला करने की बजाय येन-केन प्रकारेण शिकायत व शिकायतकर्ता को सेटलमेंट करने में लग जाते ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तंत्र में बैठे इस तरह के अधिकारियों की इस प्रवृत्ति से नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस शिकायतकर्ता, आवेदक या हितग्राही का ही होता है जो अपनी समस्या लेकर जिला प्रशासन में बैठे अधिकारियों के कार्यालयों तक चप्पलें घिसता रहता है। कई आवेदक और शिकायतकर्ताओं की स्थिति तो जिला मुख्यालय पर यह हो जाती है कि, खाया-पीया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारह आना।

अब जबकि कलेक्टर ने जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों पर भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी देने पर कार्रवाई की बात कही है तो फिर कलेक्टर को चाहिए कि वे एक आदेश और जारी कर दे कि, जो अधिकारी आवेदकों की सही समस्या का समाधान करने में आना कानी करेगा या फिर शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाएगा, या बिना निराकरण के ही ओनलाईन पोंटल पर शिकायत का निराकरण कर देने वाले उस अधिकारी पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उन आवेदकों या शिकायतकर्ताओं को थोड़ा साहस और हिम्मत मिलेगी जिनका जनसुनवाई और सीएम हेल्प लाइन पर से विश्वास उठ चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कलेक्टर की जनसुनवाई हो या सीएम की हेल्प लाइन, आमजन का विश्वास कभी बन ही नहीं पाएगी। रही बात अविश्वास पैदा करने वाले मामलों की तो ऐसे कई मामले जिले में है जिन्हे लेकर आवेदक वर्षों से कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे है और अपनी चप्पलें घिस रहे है। इनमें ज्यादातर तो वे है जो अपनी हक और मालीकी की जमीन को कब्जा मुक्त करवाना चाहते है। या फिर वे है जिन्हे अशिक्षा के कारण माफियाओं व दबंगो का शिकार होना पड़ा है।

रही बात कलेक्टर के आदेश की तो इस तरह के आदेश अच्छे है। जिससे फर्जी शिकायतकर्ताओं में खौफ पैदा होगा और जनसुनवाई में उमड़ने वाली भीड़ में कुछ कमी जरूर होगी। असल शिकायतकर्ता और आवेदकों को मजबूती मिलेगी और अगर अधिकारियों की ढीलाई ना रही तो उन्हे समस्या का समाधान भी जिला मुख्यालय पर ही मिल जाएगा। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को टटोलना भी कलेक्टर की प्राथमिकता होना चाहिए। लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों पर भी वही दंडात्मक रूख अपनाना चाहिए। जिस तरह की उम्मीद जिला प्रशासन आमजन से रखता है ठीक उसी तरह की उम्मीद आमजन जिला प्रशासन से भी करता है। वरना अब तक जिले के हालात ऐसे ही रहे है कि अधिकारियों ने हमेशा जिले में अपनी ढपली अपना राग ही गाया है। जिसके चलते शिकायतकर्ता की शिकायत और आवेदक की फरियाद दोनों ही फुटबाल बनकर रह जाते है।

पेट्रोल पम्प पर खड़े वाहनों से हुई डीजल चोरी

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी

कहा जाता है कि, कोई भी बड़ा अपराधी पहले छोटे अपराधों को अंजाम देता है और एक-एक छोटे अपराध कर वह बड़ा अपराधी बन जाता है। ऐसे में हमारी पुलिस अगर प्रत्येक छोटे अपराध पर अपनी नजर रखें और अपराध होने पर त्वरित मामला दर्ज कर आरोपी तक पहुंच कर उसे सजा दिला दे तो क्षेत्र तो क्या जिले में होने वाले बड़े अपराध हो ही नहीं। पर हर छोटी-बड़ी चोरी को पुलिस नजर अंदाज कर मामला दर्ज नहीं करती। ईसी कमजोरी के चलते क्षेत्र में आए दिन चोट्टे छोटी-बड़ी चोरी को अंजाम देते नजर आते हैं। जिसमें बाहर खड़े वाहनों से कभी बैटरी चोरी, कभी टायर चोरी तो कभी डीजल चोरी। इतना ही नहीं वाहनों में रखे टूल-बॉक्स, पाने व जेक तक की चोरियां अलग-अलग वाहनों से चोरी होना आम बात हो गई है।

खवासा पुलिस ने मौके पर आकर बनाया पंचनामा।

वही खरीफ व रबी की फसल के दौरान खेतों से मोटर, वायर, केबल, पाइप, स्टार्टर एवं आदि कृषि सामग्री चोट्टे क्षेत्र में कहीं न कहीं चोरी को अंजाम दे ही देते हैं। जिसकी चर्चा क्षेत्र में सार्वजनिक रहती है लेकिन पुलिस रिकॉर्ड बिना एफआईआर के पूरी तरह से साफ-सुथरा रहता है। यानीकि क्षेत्र में आम चर्चाओं में आए दिन इस प्रकार की चोरियों को अंजाम दिया जाता है लेकिन पुलिस रिकॉर्ड अनुसार कोई अपराध क्षेत्र में नहीं होता है।

चोरिया होने के बाद भी पुलिस रिकॉर्ड का दुरुस्त होना ही उक्त चोरियों का कारण मुख्य रूप से बना हुआ है। इन अपराधियों को जब अपनी आवश्यकता अनुसार चोरी करना होती है तो यह इतने बेखौफ होकर चोरी को अंजाम देते हैं कि, हमारे यहां कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं और चोट्टो में किसी प्रकार का कोई भय नहीं दिखता।

जिसका एक छोटा सा उदाहरण मंगलवार-बुधवार की रात में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर देखा गया। उक्त खवासा के थान्दला मार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प कमलेश रामलाल चौहान का है लेकिन संचालन दिनेश सैनिक मांडोत निवासी बामनीया द्वारा लीज पर लेकर किया जा रहा है। उक्त पम्प पर पेट्रोल पम्प के असल मालिक रामलाल चौहान का ट्रैक्टर जो पेट्रोल पम्प परिसर में खड़ा था एवं इसके साथ स्थानीय व्यक्ति की बैकहो लोडर मशीन (जेसीबी) हमेशा की तरह रात्रि में खड़ी थी।

बता दे कि, खवासा में दो पेट्रोल पम्प है और पिछले एक माह से एक या दो-दो हजार रुपए से ज्यादा डीजल नहीं दिया जा रहा है। वहीं कई बार तो तीन-तीन, चार-चार दिन तक पम्प पर डीजल-पेट्रोल ही नहीं मिलता। ऐसे में वाहन मालिक राजस्थान, गुजरात व रतलाम जिले आदि जगह से डीजल लाकर अपने वाहनों का संचालन कर रहे हैं।

वही चोर डीजल की किल्लत के साथ पेट्रोल पम्प पर खड़े वाहनों में से डीजल निकालकर चोरी को अंजाम दिया जाना चर्चा का विषय बन गया है। बैकहो लोडर व ट्रैक्टर के साथ बस व अन्य वाहन भी उक्त पेट्रोल पम्प पर रात्रि में खड़े थे। वहीं पेट्रोल पम्प के दो कर्मचारी भी सोए हुए थे कि ट्रैक्टर व मशीन के डीजल टैंक के ढक्कन के लॉक तोड़े। वही जब शायद सीधा टैंक से डीजल निकालने में असफलता मिली तो चोट्टो ने ट्रैक्टर के बेबी फिल्टर को निकाल कर करीब 40 लीटर डीजल चोरी किया गया। इसी प्रकार संजय भटेवरा की बैकहो लोडर मशीन से भी डीजल टैंक ढक्कन का लॉक तोड़ने पर डीजल चोरी करने में सफलता नहीं मिली तो डीजल टैंक के नीचे का आधा पाईप काटकर डीजल चोरी किया गया। सुबह जब ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेने पहुंचा तो ट्रैक्टर व मशीन के नीचे डीजल ढुला हुआ मिला। जिसके बाद डीजल ढक्कन को खोलने पर उसके लॉक टूटे हुए मिलें व ट्रैक्टर का बेबी फिल्टर भी निकला हुआ मिला। जिसके बाद मालिक को सूचना देने के बाद मशीन व ट्रैक्टर मालिकों ने उक्त चोरी को बड़ा अपराध मानकर पुलिस को सूचना दी। और बताया कि, पेट्रोल पम्प पर दो कर्मचारी सोए हुए थे। साथ ही यहां पैसेंजर बस भी खड़ी थी उसमें भी बस के कर्मचारी सोए हुए थे। तथा पेट्रोल पम्प पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी चोट्टो ने बेखोफ होकर वाहनों में से डीजल चोरी को अंजाम दिया। ऐसे में यह मामला बहुत बड़ा है तथा उक्त डिजल चोरी करने वाले अपराधी बाहरी न होकर स्थानीय व क्षेत्र के ही हो सकते हैं। और उक्त चोट्टे गांव व क्षेत्र में कई चोरियों को अंजाम देने के साथ ही पेट्रोल पम्प पर खड़े वाहनों में से डीजल चोरी करने की हिम्मत कर पाए हैं यह तय है।

ऐसे में उक्त डीजल चोरी के खुलासे के साथ अन्य चोरी का भी खुलासा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि, बस के कर्मचारी ने ट्रैक्टर व मशीन में से डीजल निकालते हुए देखा है। वही पम्प पर सोए कर्मचारी उक्त चोरी के दौरान नींद में सोए होने का बता रहे हैं।

सूचना पर खवासा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पम्प संचालक से मांगा गया। लेकिन समाचार लिखे जाने तक सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पम्प संचालक किसी कारणो से नहीं दे पाया है। मामले में आगे क्या होता है यह बाद में ही पता चलेगा।

रात भर चलते रहे मोरम के ट्रैक्टर

चर्चा यह भी है कि, रात भर करीब 12 से 15 ट्रैक्टरों ने मोरम ढोया। वही चर्चाओं की बात करें तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि, हो सकता है किसी ट्रैक्टर में रात में डीजल खत्म हो गया हो और किसी ने उक्त चोरी को अंजाम दिया हो। बरहाल हकीकत में असली चोर कौन है यह तो पुलिस तहकीकात के बाद ही पता चलेगा।

पेट्रोल पम्प पर खडे बैकहो लोडर मशीन व टेक्ट्रर से चोट्टो ने किया डिजल चोरी।

जल जीवन मिशन योजना अधूरी पर ठेकेदार ने बताया पूर्ण

ग्रामीणों ने की कलेक्टर से जांच की मांग, जल जीवन मिशन के नाम पर खुला भ्रष्टाचार

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

ग्राम पंचायत तारखेडी के टांडा गांव एंव ग्राम पंचायत पिठड़ी के गांव आम्बापाड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ जल मिल सके इस हेतु लाखो-करोड़ो रुपयो की पेयजल योजनाओं को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टेंडर के माध्यम से लागू की जा रही है। शासन द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ग्रामीणों को नल से स्वच्छ जल मिल सके इसलिए करोड़ों की योजनाएं शासन द्वारा संचालित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित होने वाली नल जल योजनाओं की फजीहत दिखाई दे रही है। जिसमें ठेकेदार द्वारा योजना में घटिया निर्माण कर ग्रामीणों को पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। भीषण गर्मी में ठेकेदार द्वारा योजना को चालू बताकर लाखों के बिल लगाकर राशि आहरण कर ली गई है। यह मामला है ग्राम पंचायत तारखेड़ी के गांव टांण्डा एंव ग्राम पंचायत पिठड़ी के गांव आम्बापाड़ा का जिसमें शासन द्वारा जल जीवन मिशन योजना लागू की गई है इस योजना के तहत ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिले। जिसमें नलकूप खनन एवं कूप निर्माण,पानी की टंकी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कि गई है। परंतु उसके बाद भी ग्रामीणों को हर घर नल व नल से जल नहीं मिल पा रहा है। आदिवासी अंचल में संचालित होने वाली जल जीवन मिशन योजनाओं पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है और ठेकेदारों द्वारा मनमानी की जा रही है। घटिया निर्माण व अधुरे कार्य के बावजुद योजना पूर्ण बताई जा रही है तथा ठेकेदार द्वारा बिल लगाकर पुरी राशि आहरण की जा रही है जिसकी जांच होना चाहिए। इन योजनाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में समय पर मेंटेनेंस नहीं होने पर योजनाएं बंद हो जाएगी। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है इस्टीमेंट टेंडर के मुताबिक कार्य किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है जो गंभीर जांच का विषय है। पानी की पाइपलाइन की खुदाई पूर्ण नहीं की गई, कई जगह लाइन फूट जाती है। ग्राम गरवाखेड़ी में ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कुप का निर्माण कराया गया। लेकिन कुप में पानी नहीं होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है जिसका उपयोग जलप्रदाय योजना में

नहीं हो रहा है। योजना के नाम पर ठेकेदार द्वारा जमकर पलीता लगाया जा रहा है। इन योजनाओं की ओर विभागीय अधिकारीयो का ध्यान नहीं होने से योजनाएं खटाई में पड़ी है। जिसके कारण सूखे कुप में ठेकेदार द्वारा ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। गरवाखेड़ी ग्राम में लोगों को नल स्टैंड नहीं लगाए। नलियों के माध्यम से ही जल प्रदाय हो रहा है।

टांडा गांव की महिलाओं ने बताया कि, कई घरों में नल कनेक्शन नहीं दिया पानी की परेशानी उठानी पड़ रही है। योजनाओं के नाम से लगे खुले ट्रांसफार्मर जानलेवा साबित हो रहे हैं।

क्या कहते है ग्रामवासी

वार्ड क्रमांक 19 टांडा की पंच हीराबाई मडिया गामड़ ने बताया कि, ठेकेदार ने कुप का निर्माण तो करवाया लेकिन खुला छोड दिया गया है। कुप से पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं दिया गया, पानी की टंकी में आज तक पानी नहीं गया, सीधे लाईन से जोडा गया पूरे गांव में पीने के लिए कहीं-कहीं नल स्टैंड लगाएं, कहीं-कहीं स्टैंड टूट चुके हैं। नलिया लगाकर लोगों को पानी भरना पड़ रहा है इस योजना में भ्रष्टाचार इस कदर फैला है कि, यहां देखने वाला कोई नहीं है, ट्रांसफार्मर लगाए हैं लेकिन डीपी नही हैं खुले तारो के चलते दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। कई जगह पाइपलाइन फुट चुकी है। कई कनेक्शन लोगों को देना अभी बाकी है। डेढ़ साल से योजना का काम चल रहा है आज भी काम अधूरा पड़ा है लेकिन ठेकेदार द्वारा पुरा कार्य बता कर पूर्ण राशि खर्च होना बताया है।

गांव की महिलाएं मैंना बाई, हीराबाई, शांताबाई, मंगलीया भूरिया, बाबू पुना गामड एंव ग्रामीणो ने कलेक्टर से समिति गठित कर जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत पिठडी के सरपंच गोवर्धन निनामा ने बताया कि, गांव आम्बापाडा में नल जल योजना का कार्य 1 वर्ष से अधूरा पड़ा है ठेकेदार द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए दबाव बनाया जाता है। जबकि पूरे गांव मे लाइन जगह-जगह फूट रही है नल स्टैंड नहीं लगे हैं, वाल नहीं लगे हैं ठेकेदार सुनने या बात करने को तैयार नहीं है।

वहीं संदीप जोशी ठेकेदार जी.आर.डी. सिक्योरिटी आष्टा का कहना है कि, ग्राम पंचायत तारखेड़ी के गांव टांण्डा में नल जल योजना की लागत 28 लाख रुपए की थी जो कि मेरे द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही योजना को पूर्ण कर दिया जा चुका है। जिसका मुझे ग्राम पंचायत तारखेड़ी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। मेरे द्वारा योजना को ग्राम पंचायत को हैंडओवर भी कर दी गई है। विभाग द्वारा मेरा भुगतान भी हो चुका है।

टी.एस. बामनिया उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड पेटलावद ने बताया कि, मेरे द्वारा इन ग्राम पंचायत के गांवो में स्वयं घूम कर देखा गया है नल जल योजना का कार्य पूर्ण हैं। योजना को ग्राम पंचायतो के हैंडओवर कर दिया गया है ग्राम पंचायत को संचालन व संधारण करने के लिये सूपर्द कर दिया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422